PRGI Reg. No. : CTHIN/25/A1911

हिन्दी दैनिक

लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-01 ● अंक- 205 ● भिलाई, गुरुवार 19 फरवरी 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

संक्षिप्त समाचार

हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज के साथ हादसा

अंबाला। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज आपने आवास पर गिर गए, जिससे उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। चोट लगने के बावजूद विज 'चल री सजनी अब क्या सोचेज' गुनगुनाते रहे। 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होना है। हर बार सदन में अपने तेवरों और बेबाक बयानों से सुर्खियों में रहने वाले विज इस बार शायद सदन में नजर न आएं। डॉक्टरों की सलाह को देखते हुए माना जा रहा है कि वे सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। फिलहाल समर्थक उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, जबकि खुद विज ने अपने अंदाज से साफ कर दिया है कि हौसला अब भी बुलंद है। विज विधानसभा सत्रों में कभी भी अनुपस्थित नहीं रहे। बता दें कि हाल ही में कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में मंत्री अनिल विज और एसपी उपासना के बीच एएसआई संदीप के निलंबन को लेकर तीखी बहस हुई थी।

रोहित शेट्टी फायरिंग केस में बड़ा खुलासा, इस साजिश के पीछे बिश्नोई गैंग

मुंबई। बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास पर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि इस हमले की साजिश बिश्नोई गैंग के महाराष्ट्र प्रमुख शुभम लोनकर और उसके भाई प्रवीण लोनकर ने रची थी। खास बात यह है कि प्रवीण लोनकर इस वक्त बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जेल में बंद है। इसके बावजूद उसने रोहित शेट्टी पर हमले के लिए हथियार और आर्थिक मदद मुहैया कराई। क्राइम ब्रांच को शक है कि प्रवीण लोनकर ने जेल में रहते हुए ही इस पूरे अपराध का नेटवर्क तैयार किया। पुलिस के अनुसार, इस साजिश में शामिल मुख्य शूटर समेत अब तक पुणे, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रवीण लोनकर फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और जल्द ही उसे इस मामले में औपचारिक रूप से पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक, घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, पिस्तौल और हमले के लिए जरूरी रकम प्रवीण लोनकर के निर्देश पर ही उपलब्ध कराई गई थी।

पुणे जमीन घोटाला मामले में एनसीपी नेता पार्थ पवार को दी क्लीन चिट

मुंबई। पुणे की चर्चित जमीन खरीद मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस (एनसीपी) नेता पार्थ पवार को बड़ी राहत मिली है। समिति ने पार्थ पवार को क्लीन चिट देते हुए दो सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) विकास खरगे की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने पाया कि जमीन सौदे में पार्थ पवार की सीधी अनियमितता साबित नहीं होती, हालांकि सौदे की प्रक्रिया में शामिल दो अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है।

राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम का हुआ ऐलान

26 फरवरी को नोटिफिकेशन 16 मार्च को होगा वोटिंग.......

नई दिल्ली/ एजेंसी

चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 खाली राज्यसभा सीटों को भरने के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है. 16 मार्च को मतदान होगा. चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना 26 फरवरी को जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी. उम्मीदवार 5 मार्च तक अपना पर्चा दाखिल कर सकेंगे. मतदान सुबह नौ से शाम चार बजे तक चलेगा और उसी दिन शाम पांच बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी. देर रात तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे. यह चुनाव अप्रैल की शुरुआत में खाली हो रही सीटों के लिए आयोजित किया जा रहा है. राज्यसभा की इन 37 सीटों में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से सात सीटें खाली हो रही हैं. इसके अलावा तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल से पांच-पांच सीटें रिक्त होंगी. ओडिशा से चार और असम से तीन सीटों पर चुनाव होंगे. हरियाणा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से दो-दो सीटों, जबकि हिमाचल प्रदेश से एक सीट पर मतदान होगा. इन सीटों का प्रतिनिधित्व कर रहे सांसदों का कार्यकाल 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच पूरा हो रहा है. उनके रिटायरमेंट के बाद नए सांसद शपथ लेंगे. बिहार की 5 राज्यसभा सीटें भी अप्रैल में खाली हो रही हैं. रिटायर होने वाले प्रमुख चेहरों में राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह शामिल हैं. इसके साथ ही, मोदी कैबिनेट के मंत्री रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है. आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, आरजेडी से अमरेंद्र धारी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता भी इसी लिस्ट में हैं. बिहार की इन महत्वपूर्ण सीटों पर नए चेहरों के आने या पुराने सांसदों की वापसी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. महाराष्ट्र से शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी और रामदास आठवले जैसे बड़े नेता रिटायर हो रहे हैं. तमिलनाडु से एम तंबीदुरै, तिरुचि शिवा और कनिमोझी का कार्यकाल खत्म हो रहा है. पश्चिम बंगाल से साकेत गोखले और ऋतब्रत बनर्जी जबकि असम से रामेश्वर तेली विदा होंगे. छत्तीसगढ़ से केटीएस तुलसी, हरियाणा से रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी का नाम भी शामिल है. तेलंगाना से कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी भी रिटायर हो रहे हैं. इन सभी के स्थान पर अब नए सांसदों का चुनाव होगा. राज्यसभा चुनाव को लेकर 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद नामांकन के लिए आखिरी तारीख 5 मार्च है। वहीं नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मार्च है। 16 को चुनाव होंगे। उसी दिन शाम के पांच बजे से वोटों की गिनती शुरु हो जाएगी। राज्यसभा के चुनाव लोकसभा से बहुत अलग होते हैं। यहां जनता सीधे वोट नहीं डालती। राज्यसभा के सदस्यों को राज्यों की विधानसभाओं के विधायक चुनते हैं। यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और कुछ केंद्रशासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 12 को राष्ट्रपति नामित करते हैं। हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में करीब एक-तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं, इसलिए चुनाव नियमित रूप से होते रहते हैं।

बिहार, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों का समीकरण

बिहार (5 सीटें): यहाँ जदयू के हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर, जबकि राजद के प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हालिया विधानसभा चुनावों के बाद बदले समीकरणों के कारण भाजपा और जदयू गठबंधन यहाँ मजबूत स्थिति में है।

छत्तीसगढ़ (2 सीटें): कांग्रेस की फूलो देवी नेताम और के. टी. एस. तुलसी निवृत्त हो रहे हैं। राज्य में भाजपा की सरकार होने के कारण ये दोनों सीटें भाजपा के खाते में जाने की प्रबल संभावना है।

हरियाणा (2 सीटें) व हिमाचल (1 सीट): हरियाणा में भाजपा की किरण चौधरी और हिमाचल में इंदु गोस्वामी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार होने के बावजूद पिछले राज्यसभा चुनाव के अनुभवों को देखते हुए यहाँ मुकाबला रोचक हो सकता है।

ममता बनर्जी बनाम ईडी

हवाला की जांच या टीएमसी की डेटा चोरी,कोर्ट में छिड़ा महासंग्राम

नई दिल्ली/ एजेंसी

पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपीएसी और उसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के ठिकानों पर हुई प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज पर है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर तीखी बहस हुई। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वहीं, ईडी ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि राज्य प्रशासन ने उसे आतंकित किया है। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस हाई प्रोफाइल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ईडी का मुख्य आरोप है कि 8 जनवरी को जब वे कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हवाला लिंक की जांच करने आईपैक के ऑफिस पहुंचे तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद राज्य के डीजीपी और पुलिस कमिश्नर के साथ वहां पहुंच गईं। ईडी का दावा है कि इस हस्तक्षेप से उनके वैधानिक कर्तव्यों में बाधा डाली गई। सुनवाई के दौरान बंगाल पुलिस के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने केंद्रीय एजेंसी की नीयत पर सवाल उठाए। इसके जवाब में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि ईडी किसी को डरा नहीं रही, बल्कि ममता बनर्जी के लाव-लश्कर के साथ पहुंचने से एजेंसी खुद दबाव में आ गई थी। ईडी अब ममता बनर्जी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग कर रही है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने जवाबी हलफनामे में इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका तर्क है कि वह वहां केवल इसलिए गई थीं।

इजरायली महिला से गैंगरेप-हत्या के मामले में बड़ा फैसला, कोर्ट ने तीनों दरिंदों को सुनाई फांसी की सजा

कोप्पल। कर्नाटक के कोप्पल जिले से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। गंगावती स्थित सत्र न्यायालय ने एक इजरायली महिला पर्यटक और एक होमस्टे मालकिन के साथ हुए दिल दहला देने वाले बलात्कार और हत्या के मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले तीनों दोषियों को मौत की सजा मुकर्रर की है। इन दोषियों की पहचान मल्लेश उर्फ हांडीमल्ला, साई और शरणप्पा के रूप में हुई है।

राउत ने सुनाई खरी-खोटी

चुनाव के समय ही जागता है इंडिया गठबंधन-संजय..

नई दिल्ली। लोकसभा चुनावों की आहट के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया के भीतर से ही असंतोष के स्वर उभरने लगे हैं। शिवसेना के कद्दावर नेता और सांसद संजय राउत ने गठबंधन की सुस्त रफ्तार और संवाद की कमी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गठबंधन केवल चुनाव के समय ही नजर आता है, जबकि देश के ज्वलंत मुद्दों पर नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं होती। राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का काम तभी शुरू होता है जब लोकसभा चुनाव नजदीक आते हैं। तब तक किसी के बीच कोई संवाद नहीं होता। गठबंधन में बाकी लोग क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि देश में मणिपुर हिंसा से लेकर कानून-व्यवस्था तक कई गंभीर समस्याएं हैं।

कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

सुप्रीम का फैसाला- पायजामे का नाड़ा खींचना दुष्कर्म की कोशिश

नई दिल्ली/ एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि पायजामे का नाड़ा खींचना और स्तन छूना साफ तौर पर दुष्कर्म की कोशिश है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का विवादित फैसला भी पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि नाड़ा खींचना या तोड़ना सिर्फ दुष्कर्म करने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई की और 10 फरवरी को उच्च न्यायालय के फैसले को पलटने का आदेश दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पोक्सो कानून के तहत आरोपियों के खिलाफ लगे सख्त आरोपों को भी बहाल कर दिया। 10 नवंबर 2021 को एक महिला ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि वह और उसकी 14 साल की नाबालिग बेटी उसकी ननद के घर से वापस अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान उनके गांव के ही पवन, आकाश और अशोक ने उनकी बेटी को मोटरसाइकिल पर घर छोड़ने की पेशकश की। महिला ने आरोप लगाया कि तीनों आरोपियों ने उसकी बेटी से छेड़छाड़ की और उसके पायजामे का नाड़ा भी खींच लिया। बच्ची की चीख सुनकर दो लोग वहां पहुंचे और उन्हें देखकर तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और एन वी अंजारिया की पीठ ने कहा कि विवादित आदेश आपराधिक न्यायशास्त्र के तय सिद्धांतों के गलत इस्तेमाल के कारण रद्द किया जाता है।

मोहाली में फोर्टिस अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी, सीएम मान इसी में भर्ती

मोहाली। देश में लगातार हर दिन बम की धमकियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। आज सुबह पंजाब में मोहाली के स्कूलों को फिर से उड़ाने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि ये धमकी एक मेल के जरिए दी गई है। इसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई। स्कूलों को खाली करवा दिया गया है। इस थ्रेट मेल में फोर्टिस अस्पताल का भी जिक्र किया गया है। यहां ष्टरू भगवंत मान भर्ती हैं। जानकारी के मुताबकि, सुबह साढ़े 8 बजे के करीब यह मेल आई। बता दें पिछले कल सोमवार से ही स्कूलों का समय बदला गया है। जानकारी के मुताबिक बच्चे स्कूल में पहुंच गए थे।

एक्टिव हुई यूपी पुलिस,प्रशासन-छात्रों के बीच झड़प

मोहन भागवत गो बैक के नारों से गूंज उठी लखनऊ यूनिवर्सिटी

नई दिल्ली/ एजेंसी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय बुधवार सुबह उस समय सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत वहां पहुंचे। उनके दौरे के विरोध में विभिन्न छात्र संगठनों ने कैंपस में जमकर नारेबाजी की जिसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच तीखी नोकझोंक और खींचतान देखने को मिली। लखनऊ विश्वविद्यालय में संघ के शताब्दी समारोह के सिलसिले में आयोजित एक संगोष्ठी में भाग लेने के लिए जैसे ही मोहन भागवत का आगमन हुआ, वहां पहले से तैयार छात्र संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। प्रदर्शन में एनएसयूआई समाजवादी छात्र सभा और भीम आर्मी से जुड़े छात्र बड़ी संख्या में शामिल थे। इकट्ठे हुए छात्रों ने गो बैक मोहन भागवत के नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे कुछ ही देर में कैंपस का माहौल गरम हो गया। छात्रों का तर्क था कि विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। विरोध इतना मुखर था कि पुलिस प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। हंगामे को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। पुलिस और छात्रों के बीच जबरदस्त धक्का-मुक्की और खींचतान हुई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को जबरन उठाकर जीप और बसों में भरना शुरू किया।

पीएम से मुलाकात के बाद बोले गूगल प्रमुख पिचाई

भारत एआई के क्षेत्र में असाधारण प्रगति के लिए तैयार...

नई दिल्ली/ एजेंसी

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। पिचाई भारत में आयोजित ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा लेने आए हैं और 20 फरवरी को समिट में मुख्य भाषण देंगे। भारत पहुंचने पर पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत लौटकर खुशी हो रही है और यहां हमेशा की तरह गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भारत पहुंचने पर पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत लौटकर खुशी हो रही है और यहां हमेशा की तरह गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान श्री सुंदर पिचाई से मिलकर बेहद खुशी हुई। हमने एआई के क्षेत्र में भारत द्वारा किए जा रहे कार्यों और इस क्षेत्र में हमारे प्रतिभाशाली छात्रों और पेशेवरों के साथ गूगल कैसे काम कर सकता है, इस बारे में चर्चा की। पिचाई ने कहा कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में असाधारण प्रगति के लिए तैयार है और गूगल देश के एआई परिवर्तन में साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एआई हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बदलाव है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर डायग्नोस्टिक्स से लेकर किसानों को रियल-टाइम अलर्ट देने जैसे बड़े स्तर की चुनौतियों को हल करने में सक्षम है। पिचाई ने भारत की विविधता, बहुभाषी पारिस्थितिकी और मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नवाचार के लिए मजबूत आधार बताते हुए कहा कि यह वैश्विक स्तर पर एआई के लोकतांत्रिक उपयोग का एक मॉडल बन सकता है। उन्होंने जोर दिया कि एआई का विकास भरोसे, सुरक्षा और समावेशिता को प्राथमिकता देते हुए होना चाहिए, ताकि तकनीक स्थानीय भाषाओं और संदर्भों में लोगों तक वास्तविक लाभ पहुंचा सके। इस दौरान पिचाई ने 'इंडिया-अमेरिका कनेक्ट इनिशिएटिव' की भी घोषणा की, जिसके तहत अमेरिका, भारत और दक्षिणी गोलार्ध के कई क्षेत्रों के बीच एआई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए सबसी केबल रूट विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गूगल भारत में फुल-स्टैक कनेक्टिविटी पर काम कर रहा है और भविष्य को लेकर वह बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने भारत में 15 अरब डॉलर के एआई हब की योजना का भी जिक्र किया, जिसमें गीगावॉट-स्तर की कंप्यूटिंग क्षमता और अंतरराष्ट्रीय सबसी केबल गेटवे शामिल होगा, जिससे रोजगार सृजन और उन्नत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही गूगल ने स्किलिंग कार्यक्रमों की भी घोषणा की, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी में गूगल एआई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम शामिल है, जो छात्रों और शुरुआती करियर के पेशेवरों को लक्षित करेगा। अन्य पहलों में कर्मयोगी भारत के साथ 2 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों को समर्थन, अटल टिंकरिंग लैब्स के साथ 10,000 स्कूलों में जेन एआई टूल्स की शुरुआत और 30 मिलियन डॉलर का 'एआई फॉर साइंस इम्पैक्ट चैलेंज' भी शामिल है।

अब 6जी और एआई में साथ काम करेंगे भारत-फिनलैंड, दिल्ली में पीएम मोदी और पेटेरी ओर्पो की अहम बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित 'एआई इम्पैक्ट समिट 2026' के इतर फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और फिनलैंड के बीच आर्थिक और तकनीकी संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। पीएम मोदी ने इस चर्चा को दोनों देशों के भविष्य के लिए बेहद अहम करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारत और फिनलैंड का प्राथमिक उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान स्तर से दोगुना करना है। इससे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई मजबूती मिलेगी।

CMYK

कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक की संयुक्त बैठक, दुर्घटना नियंत्रण हेतु व्यापक रणनीति तैयार

सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन सख्त

बेमेतरा। जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित व सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई एवं पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वित कार्ययोजना तैयार की गई।बैठक का मुख्य फोकस सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, नियमों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना तथा यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और अनुशासित बनाना रहा। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सड़क सुरक्षा को अभियान के रूप में संचालित किया जाए, जिसमें प्रशासन के साथ-साथ आम नागरिकों की सहभागिता भी सुनिश्चित हो।

जन जागरूकता, सख्त प्रवर्तन और आधारभूत सुधार पर जोर–'ब्लैक स्पॉट' सुधार, विशेष चेकिंग अभियान और संस्थागत भागीदारी के निर्देश 7 बैठक में दोपहिया वाहन चालकों द्वारा अनिवार्य रूप से हेलमेट उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सभी विभागों को अपने कार्यालयों में यातायात नियमों से संबंधित संदेश प्रदर्शित करने तथा कर्मचारियों को नियमों के पालन के लिए प्रेरित करने कहा गया। अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि वे स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करें और समाज में सड़क सुरक्षा के प्रति सकारात्मक संदेश दें।

दुर्घटना संभावित स्थलों का चिन्हांकन–जिले में चिन्हित दुर्घटना संभावित स्थानों (ब्लैक स्पॉट्स) का पुनर्मूल्यांकन कर वहां आवश्यक सुधार कार्य जैसे चेतावनी संकेतक, स्पीड ब्रेकर, रंबल स्ट्रिप्स और रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दिए गए। अंधेरे मोड़ों एवं व्यस्त मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने पर भी बल दिया गया 7 हेलमेट व सीट बेल्ट जांच अभियान को और प्रभावी बनाने, ओवरस्पीडिंग पर कड़ी कार्रवाई करने तथा जुर्माने की प्रक्रिया को नियमित रखने के निर्देश दिए गए। 'ड्रंक एंड ड्राइव' के विरुद्ध रात्रिकालीन विशेष अभियान चलाने तथा स्कूलों-कॉलेजों के आसपास सघन निगरानी रखने को कहा गया, जिससे नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन पर रोक लगाई जा सके। सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण हटाने, क्षतिग्रस्त स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त करने तथा मार्गों की चौड़ाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु नगर निकायों को सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया।स्कूलों, कॉलेजों तथा परिवहन क्षेत्र से जुड़े चालकों के लिए सड़क सुरक्षा कार्यशालाएं आयोजित करने की रूपरेखा भी तैयार की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जनभागीदारी के माध्यम से व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि सड़क सुरक्षा को सामाजिक आंदोलन का रूप दिया जा सके। बैठक में स्पष्ट किया गया कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन ने इस दिशा में निरंतर निगरानी एवं नियमित समीक्षा की प्रतिबद्धता दोहराई।

विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 : तीनों विधानसभा क्षेत्रों में सुनवाई कार्य समय-सीमा में पूर्ण

2,46,763 मतदाताओं को जारी नोटिस पर सुनवाई व सत्यापन प्रक्रिया पूरी

बेमेतरा। निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के अंतर्गत जिले के 03 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ङ्क 68 साजा, 69 बेमेतरा एवं 70 नवागढ़ (अ.जा.) में नो मैपिंग एवं लॉजिकल एरर श्रेणी में चिन्हित कुल 2,46,763 मतदाताओं की सुनवाई का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कर लिया गया है। प्रारंभिक प्रकाशन के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तैयारी की जा रही है। प्रारंभिक प्रकाशन के आंकड़े व तार्किक विसंगतियों पर कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप सार्वजनिक प्रकाशन एवं सुनवाई, 23 दिसम्बर 2025 को प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची के अनुसार जिले में कुल 7,16,635 मतदाता दर्ज थे। इनमें– विधानसभा 68 साजा ङ्क 2,34,247 मतदाता, विधानसभा 69 बेमेतरा ङ्क 2,28,021 मतदाता, विधानसभा 70 नवागढ़ (अ.जा.) ङ्क 2,54,367 मतदाता, प्रारंभिक सूची में 12,339 मतदाता 'नो मैपिंग' श्रेणी में पाए गए, जिन्हें नोटिस जारी कर सुनवाई की गई। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सॉफ्टवेयर आधारित 07 बिंदुओं पर तार्किक त्रुटियों (लॉजिक एरर) वाले मतदाताओं की पहचान की गई। इन सभी को विधिवत नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में तार्किक विसंगतियों से संबंधित मतदाताओं की सूची को स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायत कार्यालयों तथा ईआरओ एवं एईआरओ कार्यालयों में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया। संबंधित व्यक्तियों को 10 दिवस के भीतर व्यक्तिगत अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से दस्तावेज अथवा आपत्तियां प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए के साथ भी यह सूची साझा की गई तथा सुनवाई प्रक्रिया में उनका सहयोग प्राप्त किया गया। दावा-आपत्तियों का निराकरण पूर्ण, 21 फरवरी को अंतिम प्रकाशनभारत निर्वाचन आयोग द्वारा दावा-आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2026 निर्धारित की गई थी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देशन में यह कार्य दो दिन पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया। विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदान केन्द्रों में नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिले के 03 ईआरओ, 13 एईआरओ तथा 54 अतिरिक्त एईआरओ के माध्यम से पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपादित की गई। निर्धारित अवधि 22 जनवरी 2026 तक प्राप्त दावों में– नाम जोड़ने हेतु 7,867 फार्म-6, नाम विलोपन हेतु 711 आवेदन, स्थानांतरण एवं संशोधन हेतु 2,419 फार्म-8 प्राप्त हुए।

सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में कांग्रेस नेता के खिलाफ अपराध दर्ज

कवर्धा। जिले की सियासत में उस समय हलचल मच गई जब कांग्रेस नेता तुकाराम चन्द्रवंशी के खिलाफ तरेंगांव थाना में मामला दर्ज किया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर निर्माणाधीन सड़क को गैती से उखाड़ दिया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। वीडियो में सड़क को घटिया बताते हुए शासन प्रशासन की छवि धूमिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तकनीकी टीम को मौके पर भेजा गया। जांच के दौरान टीम ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता को मानक अनुरूप पाया। इसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई तेज करते हुए प्रकरण दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इस कोयलारी से मूधिया पथरा तक निर्माणाधीन सड़क के पर्यवेक्षण अधिकारी गौरव त्यागी ने शिकायत दर्ज कराई है कि तुकाराम चंद्रवंशी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सड़क को नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि यह सड़क बैगा बाहुल्य क्षेत्र कोयलारी से मूधिया पथरा तक लगभग

2 . 1 किलोमीटर लंबाई में बनाई जा रही है। इस निर्माण कार्य की लागत करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपये बताई जा रही है। परियोजना का उद्देश्य ग्रामीणों को बेहतर और सुगम आवागमन सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि क्षेत्र के लोगों को आवागमन में हो रही परेशानियों से राहत मिल सके।

तुकाराम चन्द्रवंशी ने की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग

दूसरी तरफइस मामले में कांग्रेस नेता तुकाराम चन्द्रवंशी ने शासन प्रशासन से सड़क निर्माण की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की मांग की है। उन्होने कोयलारी से मोंदियापथरा मार्ग को कथित रूप से गैती से क्षति पहुंचाने के आरोप में दर्ज की गई एफआईआर को पूरी तरह निराधार और तथ्यों से परे बताया है। उनका कहना है कि उन्होंने सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर केवल सवाल उठाए थे, न कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस सड़क को अधिकारी और ठेकेदार अपनी जिम्मेदारी में निर्मित बता रहे हैं, पहले यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या उक्त भूमि के लिए विधिवत वन अनुमति (फॉरेस्ट क्लीयरेंस) प्राप्त की गई थी। उन्होंने मांग की है कि यदि वन विभाग से अनुमति ली गई है तो संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं। अन्यथा यह स्पष्ट किया जाए कि निर्माण कार्य किस अधिकार के तहत कराया गया। श्री चन्द्रवंशी ने कहा कि उनके द्वारा वीडियो के माध्यम से मुद्दा उठाए जाने के बाद जांच तो कराई गई, लेकिन उन्हें विश्वास में लिए बिना पूरी प्रक्रिया संपन्न की गई, जिससे जांच की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़ा होता है। उनका कहना है कि जनता के धन से बने किसी भी निर्माण कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सड़क निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप है, तो संबंधित जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम समाप्त हो सके।

कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक

सभी अधिकारी मंगलवार एवं बुधवार को अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित रहने एवं आमजनता की समस्याओं का करें निराकरण

अधिकारियों को अवकाश में जाने पर अनिवार्य रूप से लिंक अधिकारी नियुक्त करने के दिए निर्देश

कलेक्टर ने अनिवार्य बायोमेट्रिक आधार अपडेट प्रगति की समीक्षा की

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर जिले के विभिन्न विभागों के कार्यों, समय सीमा के लंबित प्रकरणों एवं शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ गोकुल रावटे, अपर कलेक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर आर के तम्बोली, संयुक्त कलेक्टर संदीप सिंह ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर स्निग्धा तिवारी सहित जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि अवकाश पर जाने से पूर्व प्रत्येक अधिकारी

अनिवार्य रूप से सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करें तथा अपने स्थान पर लिंक अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित करें, ताकि कार्यों की निरंतरता बनी रहे। अवकाश आवेदन में लिंक अधिकारी का नाम स्पष्ट रूप से अनिवार्य उल्लेखित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राज्य शासन के निर्देशानुसार सभी अधिकारियों को मंगलवार एवं बुधवार को अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित रहकर लंबित नस्तियों का निराकरण, विभागीय समीक्षा तथा आमजनता की समस्याओं के समाधान प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त राज्य शासन के निर्देशानुसार गुरुवार एवं शुक्रवार को मैदानी स्तरों पर योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण करने कहा गया है। उन्होंने सभी अधिकारियों को शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिले के स्कूलों में मेंडेटरी बायोमेट्रिक आधार अपडेशन हेतु स्कूलों में आयोजित विशेष आधार शिविर की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त कर कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर ने निर्धारित लक्ष्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने जिले के सभी शासकीय विद्यालयों में आवश्यक बालिका शौचालयों की जानकारी ली एवं प्रस्ताव प्रस्तुत करने कहा। साथ ही मरम्मत योग्य शौचालयों की सूची शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि आगामी जनगणना का कार्य महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं आवश्यक तैयारियों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने सभी नगर पालिका सीएमओ को एपीएल से बीपीएल में नाम शामिल करने हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच कर प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिए। साथ ही खाद्य विभाग को निर्देशित किया कि एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक स्थानों पर राशन दुकान का संचालन किया जा रहा है तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने गर्मी के मद्देनजर संभावित पेयजल संकट वाले क्षेत्रों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को अग्रिम तैयारी पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या उत्पन्न होती है, वहां आवश्यक संसाधनों एवं व्यवस्थाओं की तैयारी समय से पूर्व सुनिश्चित की जाए।

जिला प्रषासन एवं पुलिस प्रषासन ने दुतकैया विवाद पर ली शांति समिति की बैठक, दोनों पक्षों ने रखे अपने-अपने विचार, सामुदायिक एकता पर जोर

गरियाबंद। ग्राम दुतकैया (खपरी) में हाल ही में दो समुदायों के बीच हुए तनावपूर्ण विवाद तथा कुछ घरों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के बाद स्थिति को सामान्य बनाने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार पहल की जा रही है। इसी क्रम में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री बीएस उइके एवं पुलिस अधीक्षक श्री वेदव्रत सिरमौर की उपस्थिति में शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों समुदायों के निवासी, पंचायत प्रतिनिधि तथा जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के

दौरान ग्रामवासियों ने घटना से उत्पन्न तनाव, नुकसान और वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा की। ग्रामीणों ने कहा कि दुतकैया में वर्षों से हिंदू-मुस्लिम सभी समुदाय आपसी सद्भाव, भाईचारा और सहयोग के साथ रहते आए हैं। उन्होंने कहा कि वे गांव में शांति की पुनर्स्थापना चाहते हैं तथा ऐसी घटनाएँ दोबारा न हों इसके लिए वे प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करेंगे।पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बताया कि घटना के तुरंत बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई, नियमित पेट्रोलिंग की गई और उपद्रवियों की पहचान कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। साथ ही कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस प्रशासन गाँव में मुस्तैद है। ग्रामीणों ने बताया कि उपद्रवियों को सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया है, जिसकी जानकारी बैठक में दी गई। समिति ने इस बात की भी सामूहिक निंदा की कि कुछ लोगों ने शांति भंग कर गांव के सौहार्द को ठेस पहुंचाई। ग्रामीणों ने अनुरोध किया कि प्रशासन ऐसे पीड़ित परिवारों को अस्थायी आवास प्रदान करे और नुकसान का आकलन कर उचित सहायता उपलब्ध कराए। ग्रामिणों ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों के कारण वे गांव गाँव छोड़कर चले गए थे वे आना चाहते हैं। कलेक्टर एवं पुलिस अधिक्षक ने प्रतिनिधिमंडल को कहा कि गांव में स्थायी शांति वातावरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अपर कलेक्टर पंकज डाहिरे, अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक धिरेन्द्र पटेल, श्री करण उइके, एसडीएम राजिम विशाल महाराणा, एसडीओपी सुश्री निशा सिन्हा, राजिम थाना प्रभारी श्री अमृत लाल साहू सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर एसपी की दो टूकः नशीली दवाओं का कारोबार युवा पीढ़ी के लिए घातक, जिले को नशामुक्त बनाने बनेगी विशेष रणनीति

बेमेतरा। जिले को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से जिला कार्यालय के सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई और पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू ने की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को समन्वय के साथ ठोस रणनीति बनाकर नशीली दवाओं के अवैध व्यापार पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने कहा कि नशापान एक सामाजिक अभिशाप है, जो समाज के ताने-बाने को भीतर से कमजोर कर देता है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आकर

अपना भविष्य बर्बाद कर रही है, जिससे पारिवारिक कलह, अपराध और सामाजिक अशांति जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों और समाज के नागरिकों से इस कुरीति को समाप्त करने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू ने कहा कि नशापान समाज में अनेक बुराइयों को बढ़ावा देता है। इससे पारिवारिक और सामाजिक जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे के अवैध कारोबार से जुड़े तस्करों और नेटवर्क के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा किसी भी स्थिति में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

नशे के हॉटस्पॉट की होगी पहचान–बैठक में निर्देश दिए गए कि जिले के उन क्षेत्रों की पहचान की जाए, जहां नशीले पदार्थों की बिक्री या खपत अधिक है।

कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने कुपोषित बच्चों और एनीमिक महिलाओ पर फोकस कर सुपोषित करने के निर्देश दिए

कलेक्टर डॉ कन्नौजे ने की महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा

गर्भवती और शिशुवती माता सहित 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण और घर पहुंच राशन शत प्रतिशत वितरित करने के निर्देश, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति शत प्रतिशत हो और उन्हें गर्म भोजन के साथ बुनियादी शिक्षा देने के निर्देश,अति जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को नहीं बैठाने के निर्देश

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों, बच्चों की संख्या, जर्जर भवन, निर्माणाधीन भवन, पूर्ण भवन, टीकाकरण, पोषक आहार वितरण आदि का परियोजना और सेक्टर अधिकारियों से चर्चा कर समीक्षा किया। कलेक्टर ने कहा कि जर्जर भवनों में बच्चों को नहीं बैठाएं। नवीन भवन निर्माण हो चुका है तो बच्चों को वहां बैठाएं। नए भवन के लिए प्रस्ताव भेजें और जर्जर भवनों को डिस्मेंटल करने के लिए भी

पत्राचार करें ताकि सभी व्यवस्थित रहे। पालकों के साथ गृह भेंट और महिलाओं के साथ चौपाल कर बच्चों के देखरेख, सावधानी आदि के बारे में माताओं को सिखाएं। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे कुपोषित और मध्यम बच्चे हैं उन्हें एनआरसी केंद्र के माध्यम से सुपोषित करने के लिए पालक को प्रोत्साहित करने सभी अधिकारी अपने अधीनस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को निर्देशित करें ताकि कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं रहे। इसी प्रकार बच्चों को जन्मजात या अन्य गंभीर बीमारी ग्रस्त है तो उन्हें चिरायु टीम को जांच करने के लिए अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी देने के लिए निर्देशित करें। उन्होंने अधिकारियों और सुपरवाइजरों को महतारी वंदन योजना के नये पंजीयन नहीं हो रहा है इसकी जानकारी अपने क्षेत्र के महिलाओं को दें। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी अधिकारी और स्टॉफ को स्पष्ट निर्देश दिए कि आपके आंगनबाड़ी का निर्माण कहाँ हो रहा है, उनके निर्माण का अच्छी गुणवत्ता से हो रहा या नहीं, यह ध्यान दें और अच्छे क्वालिटी से निर्माण नहीं हो रहा तो उसकी जानकारी उच्च अधिकारियो को दें। सभी नागरिकों के बीमारी और इलाज का रिकार्ड के लिए आभा आईडी बनाने और बच्चों के पढ़ाई का रिकार्ड रखने के लिए अपार आईडी बनाये। कलेक्टर ने कहा कि गर्भवती और शिशुवती माता सहित 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण और घर पहुंच राशन शत प्रतिशत वितरित करें। उन्होंने आंगनबाड़ी समय पर खुले और सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर को निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ कन्नौजे ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना अंतर्गत गर्भवती माताओं को लाभान्वित करें और कोई भी गर्भवती माता नहीं छूटनी चाहिए। शत प्रतिशत पोषण आहार का वितरण और पोषण ट्रैकर में इसे दर्ज होना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सेक्टर पर्यवेक्षकों द्वारा गर्भवती, शिशुवती और बच्चों के गृह भेंट के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण पोषण परामर्श सुनिश्चित करना है, उन्हें जानकारी देना है कि कौन कौन से सब्जी भाजी, फल मूल में कौन से विटामिन होता है, जिसके सेवन से शरीर मजबूत होता है। कलेक्टर ने कहा कि सेक्टर पर्यवेक्षकों द्वारा नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण होना चाहिए और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गिनती, अक्षर ज्ञान, नाम, पता, बोलने में झिझक को दूर करने के लिए स्कूल जाने के पहले बुनियादी शिक्षा देना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर ऋचा सिंह,जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी उत्तम प्रसाद सहित सारंगढ़, बरमकेला, भटगांव, बिलाईगढ़ सरसीवा, लेंधरा, कोसीर, सरिया के परियोजना अधिकारी, सेक्टर अधिकारी, सुपरवाइजर आदि उपस्थित थे।

डीईओ से मिलकर समस्याओं से अवगत कराया समन्वयक संघ

बेमेतरा। छ.ग.संकुल शैक्षिक समन्वयक संघ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला अध्यक्ष भागवत प्रसाद साहू के अगुवाई में श्री जे.आर.डहरिया डीईओ सारंगढ़ बिलाईगढ़ से मिलकर संकुल समन्वयकों एवं शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया।शाला अनुदान,सीआरसी ग्रांड की राशि,शिक्षकों का लंबित परीक्षा अनुमति, सर्विस बुक में अर्जित अवकाश को इंद्राज करने

एवं सारंगढ़ ब्लॉक में अवकाश लिए शिक्षकों के रोके गए वेतन को त्वरित जारी करने आदि समस्याओं से अवगत कराया गया।जिला शिक्षा अधिकारी श्री जे आर डहरिया ने तत्काल समाधान करने का आश्वासन दिया।इस अवसर पर जिला सचिव डाबर सिंह साहू, जिला उपाध्यक्ष राजेश कुमार देवांगन, भगवान प्रसाद दुबे,चोखलाल पटेल,नरसिंह श्रीवास, टेकलाल सोनी, पुरंदर पटेल,सुकलाल मीरी ,जीवित नायक आदि उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ का बजट 24 फरवरी को होगा पेश, वित्त मंत्री बोले- नई थीम और नए विजन के साथ आएगा बजट

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 23 जनवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी 24 जनवरी को सदन के पटल पर अपनी सरकार के तीसरे बजट को पेश करेंगे। आगामी बजट सत्र को लेकर मंत्री ओपी ने बताया कि यह उनकी सरकार का तीसरा बजट होगा, जो नई थीम और नए विजन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्री ने कहा, बजट की रणनीति 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा। 2047 के लॉन्ग टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लानिंग के तहत बजट में स्पष्ट रोडमैप देखने को मिलेगा। बजट को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, पूर्व में राजीव गांधी योजना के तहत चार किस्तों में राशि दी जाती थी, जबकि भाजपा सरकार हर साल उससे अधिक राशि दे रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पांच वर्षों में जितनी राशि नहीं दे पाई, उससे अधिक उनकी सरकार दे रही है। हर वर्ष 8000 करोड़ रुपए माता-बहनों के खातों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष केवल आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है. सरकार विकास कार्यों पर केंद्रित है, जो विपक्ष को स्वीकार नहीं हो रहा।

अब कक्षा 5वीं- 8वीं का कोई भी छात्र नहीं होगा फेल, असफल होने पर भी मिलेगा दोबारा मौका

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 5वीं- 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो गया है। 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च से शुरू होगी, जबकि 8वीं कक्षा की परीक्षा 17 मार्च से आयोजित की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा को लेकर स्पष्ट किया है कि, इस साल किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। विभाग के फैसले के मुताबिक यदि कोई छात्र मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाता है, तो उसे सप्लीमेंट्री परीक्षा का मौका दिया जाएगा। इतना ही नहीं उसमें भी सफल नहीं होने पर छात्र को अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इस साल घोषित समय-सारणी के अनुसार 5वीं की परीक्षा 16 मार्च से और 8वीं की 17 मार्च से शुरू होगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में इसी सत्र से पांचवी और आठवीं की केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित की जाएगी। साय कैबिनेट के फैसले के बाद कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा लेने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश दिया था। इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी किया गया है।

राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी को दो पालियों में 48 केंद्रों पर होगी परीक्षा

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 का आयोजन 22 फरवरी 2026 को रायपुर जिले के 48 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक एवं द्वितीय पाली दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी।परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री का वितरण जिला कोषालय, कलेक्टर परिसर रायपुर से सुबह 7 बजे एवं दोपहर 12 बजे किया जाएगा। गोपनीय परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन हेतु संबंधित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शित परीक्षा केंद्रों के लिए परिवहन अधिकारी/उड़नदस्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी नियुक्त अधिकारी निर्धारित समय पर जिला कोषालय पहुंचकर गोपनीय सामग्री प्राप्त करेंगे तथा परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटे पूर्व संबंधित केंद्राध्यक्ष को अनिवार्य रूप से सौंपेंगे।परीक्षा के दौरान आवंटित परीक्षा केंद्रों में किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु उड़नदस्ता दल द्वारा सतत निरीक्षण किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटे के भीतर परीक्षार्थियों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति की जानकारी कलेक्टर कार्यालय, कक्ष क्रमांक 06 में स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 0771-2426212 पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।परीक्षा समाप्ति के पश्चात संबंधित परीक्षा केंद्रों से गोपनीय सामग्री के सीलबंद पार्सल क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 5 को केंद्राध्यक्ष की उपस्थिति में जिला कोषालय के डबल लॉक कक्ष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के अधिकारियों ने किया कला केंद्र रायपुर का भ्रमण

रायपुर। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से आए आईएएस अधिकारियों के एक दल ने रायपुर स्थित कला केंद्र का भ्रमण किया। इस दौरान अधिकारियों ने कला केंद्र की संकल्पना, संरचना एवं यहां संचालित विभिन्न कलात्मक गतिविधियों का अवलोकन कर इसकी सराहना की।यह कला केंद्र मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशन में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा को मंच प्रदान करना तथा कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन करना है।

सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा

जनजातीय समाज का सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता

■ वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 50 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को स्वीकृति, 543 विकास कार्यों को मंजूरी

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज कोरिया जिले के बैकुंठपुर में आयोजित सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में सरगुजा संभाग के जिलों में संचालित विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा जनप्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर नई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने सरगुजा और बस्तर क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता में रखा है।प्राधिकरण के माध्यम से पिछड़े एवं वनांचल क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरगुजा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, जनजातीय समाज के सशक्तिकरण और क्षेत्र की समृद्धि के लिए सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और सभी के सहयोग से इस क्षेत्र को प्रगति के नए शिखर पर पहुंचाया जाएगा। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राधिकरण हेतु 50 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर 543 विकास कार्यों के लिए 4905.58 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई, जबकि वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 606 कार्यों को भी औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने तथा लंबित कार्यों को मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट कहा कि पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने गर्मी के मौसम में पर्याप्त पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के सोनहत विकासखंड में विद्युतीकरण का कार्य तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए, ताकि विकास योजनाओं का लाभ सीधे जनजातीय एवं वनांचल क्षेत्रों के लोगों तक पहुंच सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में हाईमास्ट सोलर लाइट लगाने, किसानों की समस्याओं के समाधान, बिजली बिल त्रुटियों को दूर करने तथा गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्राधिकरण की पिछली बैठक जशपुर जिले के मयाली में आयोजित हुई थी, जिसके बाद मयाली की पहचान पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ी है। गोल्डन बुक ऑफवर्ल्ड रिकॉर्ड्स में विश्व के बड़े शिवलिंग को स्थान मिला तथा स्वदेश दर्शन योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई। उन्होंने कहा कि बैकुंठपुर में आयोजित इस बैठक से भी जिले की पहचान और पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि झुमका जलाशय सहित यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इस प्रकार विभिन्न जिलों में बैठक आयोजित करने से स्थानीय विकास को गति मिलती है। बैठक में कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, प्राधिकरण की उपाध्यक्ष श्रीमती गोमती साय, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, सांसद श्री चिंतामणि महाराज, विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

ग्रीष्मकालीन धान के प्रति किसानों का उत्साह घटा

■ छग उद्यानिकी विभाग किसानों को धनिया की खेती के लिए कर रहा उत्साहित

■ धनिया की खेती से भूमि की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है

रायपुर। संवाददाता

छग में फसलों में अब विविधिकरण का दौर प्रारंभ हो गया है। किसानों का ग्रीष्मकालीन धान उत्पादन के प्रति उत्साह घटता जा रहा है। छग शासन कृषि विभाग द्वारा किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफेवाली फसल लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में छग शासन उद्यानिकी विभाग के संचालक द्वारा किसानों को हरी धनिया की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उद्यानिकी विभाग के कर्मचारी लगातार किसानों को संपर्क कर धनिया की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहे है। मिली जानकारी के अनुसार राजनांदगांव जिले के ग्राम डोंगरगांव, जंगलेसर एवं आसपास के गांवों में धनिया की खेती की जा रही है। जंगलेसर के किसान दौलतराम साहू ने ढाई एकड़ कृषि भूमि में धनिया की फसल लगाकर अच्छी कीमत में बेचकर नवाचार के क्षेत्र में नई पहल की है। साहू ने बताया कि उन्हें उद्यानिकी विभाग से तकनीकी मार्गदर्शन मिला। साथ ही 20 किग्राम धनिया भी अच्छी किस्म के उपलब्ध कराये गये। फसल चक्र परिवर्तन को देखते हुए उन्होंने इस बार धनिया की खेती करने का निर्णय लिया। उद्यानिकी विभाग के तकनीकी अधिकारी ने उन्हें बताया कि धनिया की खेती करने से भूमि की उर्वरक शक्ति में वृद्धि होती है एवं कम पानी का उपयोग होने से धनिया की खेती में लागत से अधिक मुनाफा मिलता है। अन्य फसलों की तुलना में धनिया में रोगों का प्रकोप कम होता है। मार्च अप्रैल माह में फल धनिया से अधिक लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि फसलों के बदलाव से अब किसानों को ग्रीष्मकालीन धान की फसल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

होली के लिए बाजार सजे, होली चार मार्च को

रायपुर। इस बार होली मार्च के प्रथम सप्ताह को पड़ रही है। होलिका दहन तीन मार्च को होगा और रंगोत्सव 4 मार्च को प्रदेशवासियों द्वारा धूमधाम से मनाया जाएगा। होली को लेकर रविवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के चिल्हर दुकानदार रंग गुलाल अबीर, पिचकारी गोल बाजार बंजारी रोड से लेते दिखाई दिया। मालवीय रोड बंजारी रोड, गोल बाजार सहित क्षेत्रिय बाजार जैसे पुरानी बस्ती, टिकरापारा, रामसागर पारा, गुढ़ियारी, रामनगर, टाटीबंध, दलदल सिवनी मोवा सड्डू सहित आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग होली की तैयारी के लिए खरीददारी करते दिखे। पिचकारी में इस बार लेटेस्ट मॉडल आए है। छोटे बच्चों के लिए रंग बिरंगी आकर्षक पिचकारियां बिकने के लिए आई है। इसी तरह दुकानदार भी होली की तैयारी के लिए अपनी अपनी दुकानें सजाना शुरू कर दिये है।

पर्यावरण और जन स्वास्थ्य की रक्षा हेतु एनजीटी जाएंग

प्लास्टिक बोतलों में शराब बिक्री से कैंसर का होगा खतरा-कन्हैया

■ सॉफ्ट ड्रिंक की प्लास्टिक बोतलों पर भी लगाई जाए रोक कन्हैया

रायपुर । संवाददाता

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने प्रदेश सरकार द्वारा प्लास्टिक की बोतलों में शराब बेचने के निर्णय पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे जनस्वास्थ्य के साथ आपराधिक खिलवाड़ बताया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल पर्यावरण को तबाह करेगा, बल्कि प्रदेश की जनता को गंभीर बीमारियों की ओर धकेलेगा। स्वास्थ्य संबंधी खतरों पर जोर देते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि: वैज्ञानिक शोधों से यह प्रमाणित हो चुका है कि प्लास्टिक बोतलों में जब शराब जैसा मादक पदार्थ लंबे समय तक रहता है, तो प्लास्टिक के सूक्ष्म कण और हानिकारक रसायन (जैसे थैलेट्स और बिस्फेनॉल-ए) शराब में घुलने लगते हैं। यह रासायनिक मिश्रण लिवर को नुकसान पहुँचाने के साथ-साथ कैंसर और बांझपन जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बनता है। सरकार राजस्व की बचत के लिए प्रदेशवासियों के जीवन को खतरे में डाल रही है। श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि करोड़ों की संख्या में एकत्रित होने वाली प्लास्टिक की बोतलों का निष्पादन असंभव है । उन्होंने मांग की कि सरकार शराब के साथ-साथ सॉफ्ट ड्रिंक (पेप्सी, कोका-कोला आदि) की प्लास्टिक बोतलों पर भी तत्काल प्रतिबंध लगाए । उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस जनविरोधी और स्वास्थ्य-विरोधी निर्णय को वापस नहीं लिया, तो इसके खिलाफ पर्यावरण विभाग और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी।

नम्रता के चेहरे में आई खुशहाली हृदय समस्या का हुआ समाधान...

■ स्क्रीनिंग के तीन दिन के भीतर ऑपरेशन, छठवें दिन हुई डिस्चार्ज

■ परिजनों ने मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन को दिया धन्यवाद

रायपुर। संवाददाता

तीन वर्षीय नम्रता बड़ी खुश है। अपने टेडी बियर से बतिया रही थी, साथ ही साथ अपनी फरारी टॉय कार को भी तेजी से घुमा रही थी। यह महसूस हो रहा था कि वह अपने दोस्त टेडी बियर के साथ किसी खूबसूरत जगह जाने का विचार कर रही है। इस खुशी का राज़ वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है उसे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि उसकी हृदय संबंधी समस्या का गतमाह सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो चुका है वह भी स्क्रीनिंग के तीन दिन के भीतर ही। यह ऑपरेशन प्रोजेक्ट धड़कन के तहत हुआ है जो मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन रायपुर द्वारा चलाया जा रहा है। नम्रता चंगोराभांटा में रहती है उसके पिता प्रशांत कुमार यादव बहुत ही सामान्य परिवार से हैं जो वाहन चालक हैं। माता मेघा यादव गृहणी हैं। पास के ही आंगनबाड़ी में उनकी बच्ची नम्रता जाती थी। आम बच्चों के साथ खेलती भी थी तभी आंगनबाड़ी में आई प्रोजेक्ट धड़कन की टीम ने 22 जनवरी को स्क्रीनिंग किया। उनके स्पेशल स्टेथोस्कोप में विशेषज्ञों को कुछ लक्षण दिखाई दिए। टीम ने नम्रता के माता-पिता को इसकी सूचना देकर एडवांस चिकित्सकीय परीक्षण की सलाह दी। पिता प्रशांत ने नम्रता को बिना देरी किए सत्य सांई संजीवनी हॉस्पिटल ले गए। 23 जनवरी को सत्य सांई हॉस्पिटल नवा रायपुर में ईको करवाया गया जहां हृदय संबंधी समस्या की पुष्टि हुई और ऑपरेशन की सलाह दी गई। प्रोजेक्ट धड़कन की टीम ने सत्य सांई हॉस्पिटल के प्रबंधन के साथ समन्वय किया, तारीख तय हुई एवं तीन दिन के भीतर ही 24 जनवरी को बच्ची का सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो गया। वह फिर से आंगनबाड़ी जा रही है व अन्य बच्चों के साथ खेल रही है।उसके पिता प्रशांत एवं माता मेघा ने मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें अंदाजा भी नहीं था हमारी बच्ची को ऐसी तकलीफहै।

सिक्किम के राष्ट्रीय विकास कार्यों का अवलोकन करेगी छत्तीसगढ़ की 12 सदस्यीय मीडिया टीम

रायपुर। सिक्किम - पत्र सूचना कार्यालय , भारत सरकार, रायपुर के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के पत्रकारों का एक 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सिक्किम के सात दिवसीय अध्ययन प्रवास पर रवाना हो रहा है । इस विशेष प्रेस टूर का उद्देश्य सिक्किम में केंद्र सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे के विकास और सामरिक महत्व के कार्यों का प्रत्यक्ष अवलोकन करना है । 15 से 21 फरवरी तक चलने वाले इस दौरे के दौरान मीडिया टीम सिक्किम की भौगोलिक चुनौतियों के बीच हो रहे इंजीनियरिंग नवाचारों और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति का दस्तावेजीकरण करेगी । इस प्रतिनिधिमंडल में छत्तीसगढ़ के प्रमुख मीडिया संस्थानों के 10 वरिष्ठ पत्रकार और पीआईबी रायपुर के एक अधिकारी व एक कर्मचारी शामिल हैं । दल का नेतृत्व सहायक निदेशक श्री सुदीप्त कर और यंग प्रोफेशनल श्री पुरुषोत्तम झा कर रहे हैं । पत्रकारों की सूची में एएनआई से संदीप प्रधान, पीटीआई से टिकेश्वर पटेल, दैनिक भास्कर से प्रमोद कुमार साहू, अमृत संदेश से संजीव कुमार वर्मा, और विस्तार न्यूज से अभिषेक तिवारी शामिल हैं । इसके साथ ही दण्डकारण्य समाचार के टीनकेश्वर तिवारी, दैनिक विश्व परिवार के हरि शंकर सोनी, समवेत शिखर के शंकर चंद्राकर, अमन पथ के रमेश पांडे और बीएसटीवी के अविनाश चंद्रवंशी भी इस अध्ययन यात्रा का हिस्सा हैं ।

जिले में पीएम आवास निर्माण ने पकड़ी रफ्तार

■ एक माह में 1628.60 लाख रुपये अंतरित

रायपुर/ संवाददाता

सरगुजा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास निर्माण कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। जिले में स्वीकृत कुल 1,02,210 आवासों में से 80,296 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, जो 50 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि को दर्शाता है। इस माह 1,781 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। निर्माण कार्यों को गति देने के लिए हितग्राहियों को किश्तों की राशि आधार आधारित डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में समय-सीमा के भीतर अंतरित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-26 में स्वीकृत 36,306 आवासों में से 18,782 आवास पूर्ण हो चुके हैं। योजना के तहत प्रत्येक हितग्राही को 1.20 लाख रुपये की राशि स्वीकृति, प्लिंथ एवं पूर्णता चरण में जियो-टैग आधारित सत्यापन के पश्चात प्रदान की जाती है। अब तक 35,125 हितग्राहियों को प्रथम किश्त (40,000 रुपये), 23,419 को द्वितीय किश्त (55,000 रुपये) तथा 10,367 हितग्राहियों को तृतीय किश्त (25,000 रुपये) जारी की जा चुकी है। विगत एक माह में 1,634 आवास पूर्ण करते हुए 1,349.05 लाख रुपये की राशि जारी की गई। साथ ही कुल मिलाकर 1,628.60 लाख रुपये हितग्राहियों के खातों में अंतरित किए गए। इसके अतिरिक्त मनरेगा के अंतर्गत 90 मानव-दिवस का मजदूरी भुगतान तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण उपरांत 12,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जा रही है। पीएम जनमन योजना के तहत जिले में 2,565 पहाड़ी कोरवा हितग्राहियों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 1,385 आवास पूर्ण हो चुके हैं। प्रति हितग्राही 2.00 लाख रुपये की सहायता राशि चार चरणों में जारी की जाती है। विगत एक माह में 73 जनमन आवास पूर्ण हुए तथा 217 लाख रुपये की राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत जिले में 1,024 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 214 आवास पूर्ण हो चुके हैं। पिछले एक माह में 74 आवास पूर्ण करते हुए 62.55 लाख रुपये की राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित की गई है। आवास निर्माण में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए 45 आवास मित्रों एवं 218 रोजगार सहायकों को कुल 61.97 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। वर्तमान में जिले में किसी भी हितग्राही की किश्त भुगतान हेतु लंबित नहीं है, जो प्रशासन की पारदर्शी एवं सक्रिय कार्यप्रणाली को दर्शाता है। आवास निर्माण से संबंधित किसी भी समस्या या सुझाव के लिए हितग्राही राज्य शासन द्वारा जारी नि:शुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-233-1290 पर संपर्क कर सकते हैं।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा हुए शामिल

तकनीक संचालित प्रशासन भविष्य की आवश्यकता-उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

रायपुर/ संवाददाता

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेकर राज्य का प्रतिनिधित्व किया। वे लीडर्स प्लेनरी सत्र में शामिल हुए और शासन-प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के प्रभावी उपयोग पर विशेष रुचि दिखाई। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सम्मेलन के दौरान एआई के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने, त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण सुनिश्चित करने तथा डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली विकसित करने के विभिन्न मॉडलों का अवलोकन किया। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में एआई के सफल उपयोग के उदाहरणों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का द्वार भारत को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह शिखर सम्मेलन भारत द्वारा ग्लोबल साउथ में आयोजित पहला वैश्विक एआई सम्मेलन है, जिसमें अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय भागीदारी देखने को मिली है। 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों, 60 मंत्रियों और 500 से अधिक वैश्विक एआई नेताओं की उपस्थिति इस आयोजन की महत्ता को दर्शाती है। श्री शर्मा ने बताया कि नीति-निर्माताओं, प्रौद्योगिकी कंपनियों, नवप्रवर्तकों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर यह सम्मेलन इंडियाएआई मिशन और डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत वैश्विक एआई विमर्श को ठोस एवं क्रियान्वयन योग्य विकास परिणामों में परिवर्तित करने का कार्य कर रहा है। उन्होंने समिट के प्रति वैश्विक उत्साह को उल्लेखनीय बताते हुए कहा कि 700 से अधिक प्रस्तावों की प्राप्ति इस बात का प्रमाण है कि पूरा विश्व भारत की एआई पहल को उत्साह से देख रहा है और सहयोग के लिए आगे आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि तकनीक संचालित प्रशासन ही भविष्य की आवश्यकता है।

संपादकीय

रूस से तेल या अमेरिका से व्यापार की राह, भारत के नए समझौते की अग्निपरीक्षा

पिछले करीब एक वर्ष से गहन विचार-विमर्श के बाद भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर आखिरकार द्विपक्षीय सहमति बन गई है। दोनों देशों की ओर से शनिवार को इसका एलान किया गया। समझौते के नियम-शर्तों के तहत अमेरिका, भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को घटाकर अठारह फीसद करेगा। वहीं, भारत की ओर से अमेरिका की सभी औद्योगिक वस्तुओं और खाद्य एवं कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर आयात शुल्क समाप्त या कम किया जाएगा।निश्चित रूप से यह समझौता दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन नफा-नुकसान का पलड़ा किस ओर भारी रहेगा, इसको लेकर अलग-अलग विश्लेषण सामने आए हैं। ऐसे में कुछ आशंकाएं और सवाल भी उठ रहे हैं कि इस समझौते को आकार देने में अड़चन कहां थी और अब ऐसा क्या हुआ कि दोनों पक्ष इसके लिए राजी हो गए। हालांकि, इस मामले में भारतीय सत्तापक्ष की ओर से स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन विपक्ष इससे सहमत नहीं है। भारत और अमेरिका ने पिछले वर्ष फरवरी में प्रस्तावित व्यापार समझौते पर पहले चरण की बातचीत शुरू की थी। कई दौर की वार्ता के बाद भी दोनों पक्षों के बीच कुछ मसलों पर आम सहमति नहीं बन पाई, जिनमें भारतीय कृषि और डेयरी बाजार में अमेरिका की पहुंच को विस्तार देने का मुद्दा भी शामिल था। दरअसल, अमेरिका शुरू से यह मांग करता रहा है कि भारतीय कृषि एवं डेयरी बाजार को उसके लिए पूरी तरह खोल दिया जाए। जबकि भारत इस मांग को खारिज करता रहा है। अब इस समझौते की जिस रूपरेखा पर सहमति बनी है, उसके मुताबिक अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों पर भारत आयात शुल्क समाप्त या कम करेगा।इससे प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि भारत ने इस मसले पर उदार रुख अपनाकर अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। माना जा रहा है कि समझौते के लागू होने से भारतीय बाजार में अमेरिका के कृषि उत्पादों की आवक बढ़ेगी, जिसका असर देश के किसानों पर पड़ सकता है। हालांकि, सरकार का दावा है कि देश के किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं और इस समझौते से उन्हें भी लाभ होगा। व्यापार समझौते की शर्तों में यह बात भी शामिल है कि भारत अगले पांच वर्ष में 500 अरब डालर के अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद, विमान एवं उसके कलपुर्जे, कीमती धातु, प्रौद्योगिकी उत्पाद और कोयला खरीदेगा। साथ ही रूस से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल खरीद बंद करनी होगी। यानी समझौते का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत इन शर्तों को पूरा कर पाता है या नहीं। इसमें दोराय नहीं कि भारतीय वस्तुओं का निर्यात, जो अमेरिकी शुल्क की वजह से प्रभावित हुआ था, वह फिर से पटरी लौट आएगा।सरकार का कहना है कि इससे तीस हजार अरब अमेरिकी डालर का बाजार खुलेगा।

कृत्रिम मेधा (एआइ) जिस तेजी से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कब्जा कर रही है, उसने सुविधाओं और चमत्कारों के साथ एक बुनियादी सवाल भी हमारे सामने रख दिया है। सवाल यह है कि इस तकनीकी उछाल को बनाए रखने के लिए बिजली कहां से आएगी? एआइ अब किसी मोबाइल ऐप या 'चैटबाट' तक सीमित नहीं रही। वह अस्पतालों में उपचार को समझने से लेकर समाधान में सहयोग दे रही है। दफ्तरों में निगरानी का यह औजार बन चुकी है। यहां तक कि सरकारी नीतियों की दिशा तय करने में शामिल हो रही है। स्थिति यह है कि आने वाले वर्षों में रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा की शक्ल बदलने वाली है। मगर जिस 'स्मार्ट भविष्य' का वादा किया जा रहा है, उसकी बुनियाद ऊर्जा पर टिकी है। आज वही सबसे कमजोर कड़ी बनती जा रही है।दरअसल, एआइ की असली ताकत बड़े-बड़े डेटा केंद्र हैं। ये ऐसे 'बिजलीखोर' कारखाने हैं जो चौबीस घंटे चलते हैं। इसके लिए हजारों कंप्यूटर, लगातार गणना, और उन्हें ठंडा रखने के लिए बेहिसाब पानी और बिजली चाहिए। आज एक बड़ा डेटा केंद्र उतनी बिजली खा जाता है जितना कि एक छोटा शहर।

जब एआई की भूख धरती से टकराई, क्या डेटा सेंटर अब अंतरिक्ष की ओर भागेंगे?

(विजन कुमार पांडेय)

भारत में, जहां बिजली और पानी पहले ही सीमित संसाधन हैं, यह दबाव और गंभीर हो जाता है। विडंबना यह है कि जिस एआइ को भविष्य की हर समस्या का समाधान बताया जा रहा है, वह खुद पर्यावरण और ऊर्जा संकट को गहरा कर रहा है। ज्यादातर डेटा केंद्र आज भी कोयला, गैस और तेल से बनी बिजली पर चलते हैं। यानी एआइ जितना 'स्मार्ट' बन रहा है, उतना ही कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ा रहा है। ऐसे में यह सवाल बिल्कुल जायज है कि क्या हम एक समस्या हल करने के प्रयास में, दूसरी बड़ी समस्या तो नहीं पैदा कर रहे?

जब जमीन पर बने डेटा केंद्र बिजली और पानी इस कदर गटकने लगे तो कई गंभीर सवाल उठे। बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने चौंकाने वाला एक विचार उछाल दिया। इन्हें धरती से हटा कर अंतरिक्ष में भेज दिया जाए। दलील है कि वहां सूरज चौबीस घंटे चमकता है, तो सोलर पैनल लगातार बिजली देंगे। ऐसे में न मौसम की मार होगी, न पानी की जरूरत। यह सारी परेशानियों का जादुई हल लगता है, लेकिन सच तो यह है कि यह समाधान नहीं, बल्कि पलायन है। बड़ी कंपनियां इस दिशा में सोच रही हैं। इसरो भी इस पर अध्ययन कर रहा है। सवाल यह नहीं कि डेटा केंद्र कहां रखें, बल्कि यह है कि बिजली की उनकी बेलगाम भूख को कौन रोकेगा।

गूगल का 'प्रोजेक्ट सन कैचर' इसी सोच पर आधारित है कि अगर उपग्रहों को बेहद सधे और समन्वित ढंग से एक समूह में चलाया जाए, तो एआइ से जुड़ा भारी गणनात्मक कार्य अंतरिक्ष में ही किया जा सकता है और धरती तक केवल जरूरी नतीजे ही भेजे जाएं। ठीक वैसे, जैसे मोबाइल पर हम सवाल पूछते हैं, लेकिन गणना कहीं और होती है। मगर यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष का विकिरण कंप्यूटर चिप्स को नुकसान पहुंचा सकता है। मगर गूगल का दावा है कि उसकी एआइ चिप्स ने अब तक के परीक्षणों में कहीं ज्यादा विकिरण झेली है, फिर भी उसने सही ढंग से काम किया है। हालांकि प्रयोगशाला की सफलता और हकीकत के बीच अब भी बड़ा फासला है।

दरअसल, डेटा केंद्र को हर समय देखभाल और मरम्मत चाहिए। धरती पर मशीन खराब हो जाए, तो इंजीनियर जाकर ठीक कर देता है, लेकिन अंतरिक्ष में यह न आसान होगा, न सस्ता। एक बार मशीन ऊपर भेज दी गई, तो उसे बदलना या सुधारना बहुत महंगा पड़ेगा। धरती पर मशीनों को ठंडा रखने की व्यवस्था की जाती हैं। अंतरिक्ष में हवा नहीं होती, इसलिए वहां गर्मी को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होगा। जबकि सूरज की तेज गर्मी लगातार पडती रहेगी। अंतरिक्ष में डेटा

केंद्र तभी संभव होंगे जब उनकी कुल लागत शोध, उपग्रह भेजने, खराब मशीनों को बदलने काम धरती पर बने केंद्रों से ज्यादा महंगी न पड़े। ऐसे प्रयोग हमेशा सफल नहीं होते। इसके पहले माइक्रोसाफ्ट ने समुद्र के नीचे डेटा केंद्र बनाने का प्रयोग किया था, ताकि ठंड की समस्या हल हो सके। शुरुआत में यह प्रयोग काफी उम्मीद जगाने वाला था, लेकिन अंत में कंपनी ने इसे छोड़ दिया। इससे यह साफ होता है कि हर नई तकनीक अंततः व्यावहारिक साबित हो, यह जरूरी नहीं। कुछ साल पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि स्टारलिंक जैसे उपग्रह इतने बड़े पैमाने पर काम कर पाएंगे। आज वे दुनिया के कई हिस्सों में इंटरनेट दे रहे हैं। इसलिए अंतरिक्ष डेटा केंद्र के विचार को पूरी तरह नकारना भी जल्दबाजी होगी। लेकिन सच तो यह है कि यह कोई समाधान नहीं, बल्कि बचने का एक रास्ता है।

असल सवाल यह नहीं है कि डेटा केंद्र बेतहाशा बढ़ क्यों रहे हैं? गांवों-कस्बों में लोग बिजली कटौती झेल रहे हैं, खेतों के लिए पानी नहीं मिल रहा और शहरों में मशीनें चौबीस घंटे बिजली फूंक रही हैं। ऐसे में उन्हें आसमान में भेज देने से समस्या खत्म नहीं होगी, बस नजर से ओझल हो जाएगी। धरती पर पैदा की गई मुसीबत का जवाब अगर अंतरिक्ष में ढूंढ़ा जाएगा, तो यह तरक्की नहीं, जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना ही कहलाएगा। जब तक एआइ की ऊर्जा भूख को काबू में करने की ईमानदार कोशिश नहीं होगी, तब तक 'स्मार्ट भविष्य' आम लोगों के लिए राहत नहीं, बल्कि एक और बोझ ही साबित होगा।

आज भी किसी मशीन को अंतरिक्ष में भेजना बेहद महंगा है। डेटा केंद्र कोई छोटा उपग्रह नहीं, बल्कि भारी और जटिल ढांचे होते हैं, जिन्हें लगातार मरम्मत चाहिए। विकिरण और तापमान से बचाने के लिए अलग तकनीक चाहिए, यानी अरबों-खरबों का निवेश। ऐसे में सवाल यह है कि इसकी कीमत कौन चुकाएगा, जनता, उपभोक्ता या सरकार? दूसरा बड़ा सवाल सुरक्षा का है। धरती पर 'सर्वर' खराब हो, तो उसे ठीक किया जा सकता है। अंतरिक्ष में हर खराबी जोखिम बन जाती है। ऊपर पहले से ही मलबा भरा है। ऐसे में विशाल डेटा केंद्र भी टकराव का खतरा बनेंगे और फिर एक हादसे से पूरी व्यवस्था ठप हो सकती है।

तीसरा और सबसे जरूरी सवाल आम आदमी का है। इससे उसकी बिजली सस्ती होगी या बिल और बढ़ेंगे? पर्यावरण बचेगा या अंतरिक्ष भी कंपनियों की प्रयोगशाला बन जाएगा? डर यह है कि अंतरिक्ष में डेटा केंद्र का मतलब होगा- कुछ गिने-चुने हाथों में और ज्यादा ताकत तथा आम लोगों से और दूरी।

असल सवाल यह नहीं है कि डेटा केंद्र अंतरिक्ष में बनाए जा सकते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि हम धरती पर गलत तकनीकी आदतें सुधारना चाहते हैं या नहीं। एआइ को कम बिजली पर चलने वाला बनाना, बेहतर चिप विकसित करना और सौर-पवन जैसी ऊर्जा अपनाना कहीं अधिक व्यावहारिक रास्ता है। एआइ इंसान की बनाई तकनीक है, जिसकी रफ्तार और सीमा तय करना हमारे ही हाथ में है। अगर हर नया माडल पहले से कई गुना अधिक बिजली मांगता है, तो यह तरक्की नहीं, चेतावनी है। अंतरिक्ष में डेटा केंद्र का विचार इसी चेतावनी का संकेत है कि संतुलन न बना, तो भविष्य महंगा और जोखिम भरा होगा। दरअसल, एआइ की तेज होती रफ्तार अब धरती की सीमाओं से टकराने लगी है। बिजली, पानी और पर्यावरण पर बढ़ता दबाव बड़ी तकनीकी कंपनियों को अंतरिक्ष की ओर देखने के लिए मजबूर कर रहा है। अंतरिक्ष में डेटा केंद्र का विचार इसी बेचैनी की उपज है। यह तकनीकी कल्पना जितनी आकर्षक दिखती है, उतने ही गहरे सवाल भी खड़े करती है- लागत, सुरक्षा और नियंत्रण का। असली चुनौती यह है कि एआइ की बढ़ती ऊर्जा भूख पर लगाम कैसे लगे। अगर तकनीक आम लोगों की जिंदगी आसान करने के बजाय संसाधनों पर बोझ बनने लगे, तो दिशा पर फिर से सोचने की जरूरत है। ऐसे में भविष्य आसमान में नहीं, समझदारी में छिपा है।

नींद जिसे हम गंवाना समझते हैं, वही है सेहत की असली दौलत

(सरस्वती रमेश)

प्रकृति प्रदत्त नेमतों की कोई कीमत नहीं। वे अनमोल होती हैं। अब नींद को ही देखा जाए। हमारे आसपास ऐसे लोग आम हैं, जिनकी नजर में सोना वक्त गंवाना है। 'जो लोग सोते हैं, वे खोते हैं', इस आशय से कई कहावतें और उक्तियां भी हैं। अगर कोई व्यक्ति सोता हुआ दिख जाता है, तो उसे उसके बिगड़े हुए काम का कारण बताया जाता है। कुछ स्थितियों में यह सच भी हो सकता है। एक गरीब आदमी को नींद की जितनी जरूरत होती है, उतनी ही उन्हें भी, जिनके घरों में रुपए बोरियों में भरे हुए हैं। भोजन पानी की तरह नींद भी दुनिया में रहने वाले हर शख्स की जरूरत है। नवजात बच्चे जितना ज्यादा सोते हैं, उतनी ही तेजी से बढ़ते हैं। बच्चे ही क्यों, बड़ों को भी नींद की उतनी ही जरूरत होती है। अब सवाल यह उठता है कि हमें नींद की जरूरत पड़ती क्यों है।

सोना जितना दिमाग के लिए जरूरी होता है, उतना शरीर के लिए भी। आमतौर पर हमें लगता है कि जब हम सो जाते हैं, तो हमारा दिमाग भी थककर सो जाता होगा। मगर ऐसा नहीं है। सोते समय हमारा दिमाग जीने के लिए जरूरी कई क्रियाकलापों में लग जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के काम में सीधे तौर पर जुट जाता है, जो हमारे जागते हुए दिमाग के लिए करना संभव नहीं होता है।

इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर हमने कभी रात को अपनी नींद खराब की होगी, यानी किसी वजह से हम रात को सो नहीं पाए होंगे, तो अगले दिन अजीब-सी थकान या तनाव का अहसास होता है। काम करने में भी दिमाग का भरपूर इस्तेमाल नहीं हो पाता।

इसकी वजह यह है कि नींद का हमारे दिमाग की कार्यक्षमता से संबंध होता है। नींद दिमाग के काम करने के तरीके पर असर डालती है। दिमाग को लचीलेपन यानी संकेतों के हिसाब से ढलने की क्षमता के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। अगर हम बहुत कम सोते हैं, तो दिन में सीखी हुई चीजों को अपने भीतर स्थिर नहीं कर पाते और भविष्य में उन्हें याद रखने में ज्यादा दिक्कत होती है।

शोधकर्ताओं का कहना है कि नींद दिमाग की कोशिकाओं से बेकार चीजों को हटाने में मदद करती है। जब दिमाग क्रियाशील होता है, यानी हम जाग रहे होते हैं, तो यह काम उतनी कुशलता से नहीं हो पाता है, लेकिन सोने के बाद दिमाग पर से अतिरिक्त भार खत्म हो जाता है और वह खुद को व्यवस्थित करने की क्रिया में जुट जाता है।

दिमाग के अलावा नींद बाकी शरीर के लिए भी बहुत जरूरी है। जब लोगों को पर्याप्त नींद नहीं मिलती, तो तरह-तरह की बीमारियां पकड़ने के खतरे बढ़ जाते हैं। अवसाद, दौरे, उच्च रक्तचाप और सिरदर्द के लक्षण और बढ़ने लगते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे बीमारी और संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है।

नींद चयापचय में भी भूमिका निभाती है। यह जानकर हैरानी होगी कि एक रात की नींद छूटने से भी एक स्वस्थ व्यक्ति में मधुमेह-पूर्व की स्थिति बन सकती है।

वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हम सोते हैं, तब हमारा दिमाग दो अलग-अलग तरह की नींद लेता है। आरइएम (रैपिड-आइ मूवमेंट) नींद और गैर-आरईएम नींद। नींद की प्रक्रिया का पहला हिस्सा नान-आरईएम नींद है, जिसके चार स्तर होते हैं। पहला स्तर जागने और सोने के बीच का होता है।

दूसरा हल्की नींद होती है, जब दिल की धड़कन और सांस लेने की गति नियमित हो जाती है और शरीर का तापमान कम हो जाता है। तीसरे और चौथे स्तर में गहरी नींद होती है। पहले यह माना जाता था कि आरईएम नींद सीखने और याददाश्त के लिए सबसे जरूरी नींद का चरण है, लेकिन नए आंकड़ों से पता चला है कि गैर-आरईएम नींद इन कामों के लिए ज्यादा जरूरी है। यह नींद शरीर को अधिक आराम पहुंचाने वाली होती है। यह चक्र चलता रहता है, लेकिन हर चक्र के साथ हम नींद के गहरे स्तर तीन और चार में कम समय और आरईएम नींद में ज्यादा समय बिताते हैं। एक रात में हम चार या पांच बार इस चक्र से गुजरते हैं। नींद का विज्ञान कुछ भी कहे। लेकिन हमारा अनुभव यह कहता है कि अच्छी नींद हमारे स्वस्थ रहने की कुंजी है।

इसलिए कुछ भी हो जाए, नींद से समझौता नहीं होना चाहिए। नींद का चक्र अगर बाधित होता है, तो यह हमारी सेहत और व्यक्तित्व को बाधित कर दे सकता है।

विश्व व्यापार में भारत की छलांग, पर जमीन पर बढ़ रही हैं कई चुनौतियां

दुनिया भर में विकसित देशों के लिए भारत एक विशाल उपभोक्ता बाजार, निवेश का भरोसेमंद ठिकाना और रणनीतिक साझेदारी का प्रमुख केंद्र है। अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने यह समझा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। इन देशों के लिए भारत का सबसे बड़ा आकर्षण इसका विशाल मध्यम वर्ग, बढ़ती खपत क्षमता और युवा आबादी है, जो आटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक्स, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं की मांग को लगातार बढ़ा रही है।

(ब्रह्मदीप अलूने)

दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजारों में शामिल भारत की कम लागत वाली कुशल श्रमशक्ति और विशाल बाजार पूंजीवादी शक्तियों की आर्थिक महत्वाकांक्षी योजनाओं को साकार करने के लिए मुफीद नजर आते हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर शुल्क कम करने की अचानक घोषणा ने सबको चमत्कृत किया है, वहीं अमेरिकी प्रशासन को चुनौती देकर यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता अभूतपूर्व माना जा रहा है। भारत को यह उम्मीद है कि विकसित देशों के साथ व्यापार से दीर्घकालिक लाभ होंगे। अमेरिका और यूरोप में क्रय-शक्ति अधिक है और वे गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए ऊंची कीमत देने को तैयार रहते हैं।

इससे भारत के दवा उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, कपड़ा उद्योग, वाहन पुर्जे, इंजीनियरिंग सामान, रत्न तथा आभूषण और कृषि-प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को विस्तार मिल सकता है। विकसित देशों के साथ व्यापार और समझौते भारत में विदेशी निवेश बढ़ा सकते हैं, जिससे उत्पादन क्षमता, रोजगार और आधुनिक तकनीक का हस्तांतरण संभव होता है। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका मजबूत कर सकता है।

विकसित देशों की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं और पूंजीवादी समाज के साथ कदमताल मिलाते भारत के विकासशील समाज के लिए चुनौतियां भी कम नहीं हैं। विकसित देश यानी पूंजी, तकनीक, प्रति व्यक्ति आय, बचत, निवेश और नागरिकों के रहन-सहन जैसी विशेषताओं में उच्च स्तर और मजबूत अर्थव्यवस्था। जबकि विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है, राष्ट्रीय आय के अनुपात में बचत और निवेश का निम्न स्तर होता है।

अधिक जनसंख्या होती है, लेकिन वह कम कार्यकुशल होती है। पूंजी निर्माण की दर कम तथा आयात की मात्रा अधिक रहती है। इन देशों में पूंजी और तकनीकी का आमतौर पर दूसरे देशों से आयात होता है। विकासशील देशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि में संलग्न रहता है, फिर भी उत्पादन देश की आवश्यकता से कम बना रहता है।

विकसित देशों को कच्चा माल, श्रम-आधारित उत्पाद चाहिए, जबकि विकासशील देशों को पूंजी, तकनीक, मशीनें और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद चाहिए। इसलिए दोनों का व्यापार अक्सर जरूरतों की पूर्ति पर आधारित होता है। ऐसे में भारत द्वारा विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना भविष्य में आर्थिक अवसरों के साथ कुछ रणनीतिक जोखिम भी पैदा कर सकता है।

विकसित देशों की कंपनियां, तकनीक, पूंजी और ब्रांड के दम पर भारतीय बाजार में तेजी से प्रवेश करेंगी, जिससे छोटे किसान और घरेलू उद्योग दबाव में आ सकते हैं। सस्ते आयात से व्यापार घाटा बढ़ने, स्थानीय उत्पादन कमजोर होने और रोजगार पर असर का खतरा भी रहेगा। इसके अलावा, पेटेंट, डेटा, पर्यावरण और श्रम मानकों जैसी शर्तें भारत की आर्थिक और राजनीतिक निर्णय की स्वतंत्रता सीमित कर सकती हैं।

बीते चार दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं। इसमें विश्व व्यापार संगठन की नीतियों का भी बड़ा और सकारात्मक

लाभ मिला है। वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद वैश्विक व्यापार नियमों में एकरूपता आई, व्यापार बाधाएं कम हुई और विभिन्न देशों के बीच बाजार तक पहुंच आसान बनी।

भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह अवसर था कि वह अपनी आर्थिक क्षमता, श्रमशक्ति और सेवा क्षेत्र की ताकत के आधार पर वैश्विक मंच पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए। विश्व व्यापार संगठन ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में विकसित देशों के कब्जे को रोकने के लिए अनुचित सबसिडी, डंपिंग और व्यापार बाधाओं पर नियम बनाए। इसका लाभ भारत जैसे विकासशील देश को निर्यात विस्तार के रूप में मिला।

विश्व व्यापार के तहत आयात शुल्क घटाने और व्यापार को अधिक पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया ने भारतीय उत्पादों के लिए नए बाजार खोले। विश्व व्यापार संगठन और मुक्त व्यापार समझौते वैश्विक व्यापार को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन इनके स्वरूप, उद्देश्य और प्रभाव में मूलभूत अंतर है। यही अंतर विकसित और विकासशील देशों के बीच व्यापार संबंधों में एक प्रकार का विरोधाभास पैदा करता है। विश्व व्यापार संगठन एक बहुपक्षीय संस्था है, जो नियम आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था को स्थापित करती है, जबकि मुक्त व्यापार समझौता चुनिंदा देशों के बीच विशेष रियायतों और शर्तों पर आधारित क्षेत्रीय या द्विपक्षीय व्यवस्था है। इस कारण विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच व्यापार में समानता से कहीं ज्यादा असंतुलन बढ़ता दिखाई देता है। दूसरी ओर, मुक्त व्यापार समझौते बिल्कुल अलग हैं। मुक्त व्यापार समझौते में कुछ देश आपस में शुल्क घटाकर या समाप्त करके व्यापार को तेज करते हैं। विकसित देशों के लिए मुक्त व्यापार समझौते अक्सर एक रणनीतिक हथियार बन जाते हैं। वे विश्व व्यापार संगठन में जब व्यापक सहमति नहीं बना पाते, तब मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से अपने हितों को आगे बढ़ाते हैं। विकसित देश मुक्त व्यापार के नाम पर केवल शुल्क घटाने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पेटेंट नियम, डेटा स्थानीयकरण पर रोक, श्रम और पर्यावरण मानकों की कठोर शर्तें, सरकारी खरीद में विदेशी कंपनियों को अवसर तथा निवेश विवाद निपटान जैसी शर्तें जोड़ देते हैं। इन शर्तों का असर यह होता है कि विकासशील देशों की आर्थिक नीतियों को लेकर स्वतंत्रता सीमित होने लगती है। पूंजीवादी शक्तियों का प्रभाव राजनीतिक रूप से भी पड़ने की संभावना बढ़ जाती है और यह स्थिति भारत जैसे विकासशील और लोकतांत्रिक देश की चुनौतियां बढ़ा सकती है। व्यापार को लेकर नए समझौतों से अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में भारत की पहुंच बढ़ने से निर्यात में वृद्धि होगी, विदेशी निवेश और तकनीक हस्तांतरण के अवसर भी मिलेंगे। वहीं विकसित देशों की विशाल कंपनियां कम शुल्क के साथ घरेलू बाजार में प्रवेश करेंगी, तो भारत के छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योग तथा कृषि क्षेत्र पर दबाव बढ़ सकता है। दरअसल, विकसित देश नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था की बात करते हुए भी अपने हितों के लिए क्षेत्रीय समझौतों का सहारा लेते हैं। भारत और विकसित देशों की प्राथमिकताओं में गहरा अंतर है। भारत की मुख्य चिंता गरीबी घटाना, रोजगार बढ़ाना, कृषि और ग्रामीण विकास, सस्ती शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक न्याय की स्थापना है। वहीं विकसित देशों की प्राथमिकताएं उच्च जीवन-स्तर, तकनीकी नवाचार, पर्यावरण मानक, कड़े श्रम नियम और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ी हैं। जाहिर है, भारत और विकसित देशों की नीतियां और दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि वह मुक्त व्यापार को सुरक्षा-कवच, चरणबद्ध उदारीकरण और घरेलू क्षमता-वृद्धि के साथ संतुलित रूप में लागू करे। भारत के स्थायी विकास के लिए रोजगार सृजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास, उद्योगों का विस्तार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक सुधार अत्यंत आवश्यक हैं। इन्हीं आधारों पर देश की आर्थिक मजबूती, सामाजिक संतुलन और दीर्घकालिक प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है।

माता मावली मेला के समापन अवसर पर पहुंचे सांसद महेश कश्यप, देवी देवता और संस्कृति को सहेजकर रखने की दी सुझाव

सांसद कश्यप ने रील प्रतियोगिता के विजेताओं को किया सम्मानित, युवाओं की प्रतिभा को सराहा

माता मावली मेला में अलंकार बैंड बिलासपुर की प्रस्तुति ने बटोरी सुर्खियां

नारायणपुर। जिले में माता मावली मेला 2026 के अंतिम दिवस का आयोजन अत्यंत भव्य एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सांसद श्री महेश कश्यप ने नारायणपुर की जनता एवं सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति और परंपरा हमारी पहचान है, जिसे सदैव संरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने बताया कि वन मंत्री केदार कश्यप द्वारा माता मावली मेला को उत्सव का दर्जा प्रदान किया गया है और अब इसे माता मावली उत्सव के रूप में आयोजित किया जाएगा। सांसद कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात में माता मावली मेला नारायणपुर का उल्लेख कर इसकी सांस्कृतिक महत्ता को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि माता मावली मड़ई क्षेत्रीय लोक संस्कृति, परंपरागत आस्था और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जिसका निर्वहन सैकड़ों वर्षों से किया जाता रहा है। राज्य शासन द्वारा लोक कला और परंपराओं के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष रूपसाय सलाम, जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम तथा नगर पालिका अध्यक्ष इंद्रप्रसाद बघेल ने भी संबोधित करते हुए मेले की गरिमा और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। माता मावली मेला के अवसर पर आयोजित रील प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। सांसद महेश कश्यप द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले हर्षित नेताम को 20 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई। द्वितीय स्थान नाशिक सहारे को 10 हजार रुपये तथा तृतीय स्थान चमन कचलाम को 5 हजार रुपये की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया।कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बिलासपुर से आए अलंकार बैंड की शानदार प्रस्तुति रही, जिसने अपनी मनमोहक धुनों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरे आयोजन ने सांस्कृतिक एकता, परंपरा और उत्साह का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया।इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष पिंकी उसेंडी, जनपद पंचायत ओरछा के उपाध्यक्ष मंगडू नुरेटी सहित जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर नम्रता जैन, पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुरिया, जिला पंचायत सीईओ आकांक्षा शिक्षा खलखो, अपर कलेक्टर बीरेंद्र बहादुर पंचभाई, एसडीएम अभयजीत मांडवी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग राजेंद्र सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी आशीष कोर्राम सहित पार्षदगण एवं बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित थे।

कांकेर में सी.जी.पीएससी अभ्यर्थियों हेतु प्रेरणात्मक कार्यशाला, कलेक्टर व सीईओ ने दिया सफलता का मंत्र

कांकेर। जिले में प्रतिभाओं को नई दिशा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा मावा मोदोल सशक्त सेंटर लाइब्रेरी कोचिंग केंद्र, कांकेर में पीएससी अभ्यर्थियों के लिए विशेष मोटिवेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने अपने प्रेरणादायी एवं ओजस्वी संबोधन से विद्यार्थियों में नई ऊर्जा का संचार किया। कलेक्टर क्षीरसागर ने कहा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन, निरंतरता और आत्मविश्वास की भी परीक्षा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लक्ष्य बड़ा हो तो मेहनत भी उसी स्तर की होनी चाहिए। उन्होंने अभ्यर्थियों को प्रतिदिन नियोजित अध्ययन, विषयों की गहन समझ, नियमित मॉक टेस्ट और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण अनुभव है। यदि विद्यार्थी सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ तैयारी करें तो सफलता निश्चित है। कलेक्टर ने जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि प्रशासन ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को हर संभव संसाधन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। मावा मॉडल निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से जिले की प्रतिभाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु सक्षम बनाया जा रहा है। जिला पंचायत सीईओ हरेश मंडावी ने भी अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए नियमित रिवीजन, करंट अफेयर्स पर विशेष पकड़ और संतुलित दिनचर्या बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने जानकारी दी कि पीएससी प्रारंभिक परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को आगे की तैयारी हेतु जिला प्रशासन द्वारा निःशुल्क आवासीय कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी, डीएमसी सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। संवाद सत्र में अभ्यर्थियों ने अपने प्रश्न रखे और अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त किया।

निकासी बैठक में अनियमितताओं पर सख्ती, 20 पंचायतों से वसूली

5 रोजगार सहायकों और एक तकनीकी सहायक पर अर्थदंड

बीजापुर। जनपद पंचायत के सभाकक्ष में सामाजिक अंकेक्षण से जुड़ी अनियमितताओं पर कार्रवाई को लेकर निकासी बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम जागेश्वर कौशल ने की। इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक महात्मा गांधी नरेगा और प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजनाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में हुए सामाजिक अंकेक्षण के दौरान सामने आए मामलों की सुनवाई कर निराकरण किया गया। बैठक में 26 पंचायतों के ऑडिट प्रकरणों की समीक्षा की गई। जांच के बाद करीब 20 पंचायतों से वसूली के निर्देश दिए गए, जबकि पांच पंचायतों के रोजगार सहायकों और एक तकनीकी सहायक पर अर्थदंड लगाया गया। वसूली की राशि एक ग्राम पंचायत में 623 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक तय की गई, वहीं प्रकरणों के अनुसार 200 से 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया।जिन पंचायतों से वसूली की गई, उनमें नैमेड, तुमनार, पापनपाल, मिडते, चेरपाल, मुसालूर, दुगोली, बोरजे, धनोरा, कैका, ईटपाल, मनकेली, कांडुलनार, गंगालूर, कमकानार, चिन्नाकवाली, मोरमेड़, तोयनार, संतोषपुर और पेदाकोडेपाल शामिल हैं।

दो विभागों को चेतावनी जारी करने के निर्देश-सोशल ऑडिट टीम ने बताया कि चिन्नाकवाली ग्राम पंचायत में उद्यानिकी विभाग द्वारा कराए गए कार्यों में आपत्तियां दर्ज की गई, लेकिन निराकरण के लिए लगातार पत्राचार के बावजूद अपेक्षित सहयोग नहीं मिला।

इसी तरह कृषि विभाग पर भी ऑडिट प्रक्रिया में लापरवाही का आरोप लगा। इस पर एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सभी अभिलेख प्रस्तुत कर ऑडिट में सहयोग करने के निर्देश दिए। तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर राशि वसूली की चेतावनी भी दी गई। बैठक में उपसंचालक पंचायत हिमांशु साहू, सहायक परियोजना अधिकारी मनीष सोनवानी, कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र गवेल सहित तकनीकी सहायक, सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक मौजूद रहे।

यूजर चार्ज के नाम पर असंवैधानिक वसूली बंद करें महापौर,बिना शासन के निर्देश बिना किसी सामान्य सभा स्वीकृति के राशि वसूलना अनैतिक कृत्य,होगा पुरजोर विरोध: राजेश चौधरी

अस्थाई व फुटपाथ व्यापारियों से यूजर चार्ज लेने हेतु शासन निर्देश हैं तो विधिवत महापौर परिषद और सामान्य सभा में विषय लेकर आए महापौरः राजेश चौधरी

जगदलपुर। नगर पालिक निगम जगदलपुर के नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जगदलपुर विधायक किरण देव महापौर संजय पांडे कांग्रेस पार्टी को धर्म विरोधी मंदिर विरोधी बोल बोल कर जनता से वोट लेकर सत्ता हासिल करने वाले ढोंगियों की सरकार में आज महाशिवरात्रि के दिन शिवालयों के सामने इतने वर्षों से सफाई के बाद चुना डाला जाता था ट्रिपल इंजन की सरकार में आज शिवालयों के सामने सफाई के बाद चुना डालने की हैसियत नहीं बची है जबकि प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के दिन शिवालयों के सामने सफाई के बाद चुना डाला जाता था दीपोत्सव के लिए चंदा लेने वाली निगम सरकार शिवरात्रि के पहले कम से कम शिवालयों के सामने ऐसी व्यवस्था देने के लिए भी चंदा मांग लेते। क्योंकि सरकार के पास धार्मिक कार्यों के लिए अब पैसा नहीं बचा है और धर्म के ठेकेदारों को भी भाजपा के नकारा सरकार की कमियां नहीं दिखती है एक तरफ महापौर खुद को धर्म का हितैषी बताते हैं और दूसरी ओर धार्मिक कार्यों के लिए सरकारी सहयोग से पल्ला झाड़ते हुए आम नागरिकों और संस्थाओं से चंदा मांगने का काम करते हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने आगे बताया जिन फुटपाथ के फुटकर व्यापारियों से सरकार द्वारा अस्थाई दखल चार्ज लेना बंद कर दी थी आज उन्हीं फुटपाथ के फुटकर व्यापारियों से यूज़र चार्ज के नाम पर अनाप-शनाप वसूली की जा रही है जिस संबंध में किसी प्रकार का कोई सकारात्मक जवाब ना महापौर परिषद ना निगम प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है जबकि नियम है कि कोई भी कर लागू करने से पूर्व राज्य सरकार के निर्देशानुसार महापौर परिषद और सामान्य सभा से पारित करके किया जाता है जो यूज़र चार्ज वार्षिक लिया जाता था अब सनातनी महापौर बनने के बाद निगम प्रशासन के द्वारा मासिक वसूली की जाने की बात वसूली करने वाले कर्मचारी द्वारा बताई जा रही है और महापौर जी को यह वसूली जायज लगती है क्योंकि वह स्वयं महापौर बनने के बाद लगातार शहर की जनता को आर्थिक चोट देते आ रहे हैं जैसे 300 का पानी टैंकर 500 हो गया 500 वाला पानी टैंकर 1000 हो गया सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों में निशुल्क दिए जाने वाला टैंकर का 500 लगेगा यदि स्टोरेज करेंगे तो 300 लगेगा। तरण ताल में बच्चों का टिकट चार्ज?50 और बड़ों का ?100 निर्धारित था आज उसे बढ़ाकर बच्चों का ?100 और बड़ों का ?200 किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास का लाभ लेने वाले बीपीएल परिवारों को संपत्ति कर के दायरे में नहीं लिया जाना है परंतु महापौर जी के निर्देशानुसार उन गरीब परिवारों को जिन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है आज उन्हें संपत्ति कर दाता बना दिया गया है और अब उनसे जल कर भी 60/ङ्क प्रतिमाह के जगह 200/ङ्क प्रतिमाह लेंगे। यदि प्रधानमंत्री आवास का लाभ लेने वाले परिवार 300 वर्ग फुट से अधिक में निर्माण कार्य करते हैं तो अधिक निर्माण क्षेत्र का माप लेकर उनसे संपत्ति कर लिया जाना चाहिए परंतु इस दिशा में बिना किसी निर्देश बिना किसी मापदंड के सभी गरीब प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों से संपत्ति कर लिया जाना न्याय संगत नहीं है महापौर जी और राजस्व सभापति कहते हैं की दर नहीं बड़े हैं रीएसेसमेंट के कारण से कर बढ़ गया है तो महापौर जी को जनता को यह भी बता देना चाहिए की किन परिवारों का रिएसेसमेंट पहले गलत लिया गया था और अभी सही लिया गया है और पहले उन्हें कौन सा दर लगा था और अभी कौन सा दर लगा है क्योंकि कई मकानों में तीन-तीन गुना टैक्स लगा दिया गया है जबकि उन हितग्राहियों के द्वारा कोई नया निर्माण नहीं किया गया है विधायक जी महापौर जी भूल गए हैं की यही जनता उनके लिए कुछ लाभदायक कार्य होगा सोच कर अपना वोट देकर इन्हें पदासीन किया है,उन्हें क्या मालूम था कि उनके पद में बैठने के बाद सबसे पहले आर्थिक चोट उन्हें ही मिलेगी,जिन्होंने अपना वोट देकर इन्हें सत्ता में बिठाया है। हमने आयुक्त नगर निगम जगदलपुर महापौर नगर निगम जगदलपुर और कलेक्टर महोदय को पत्र लिखकर इन सारे मांगों पर तत्काल जांच कर नियमतः संपत्ति कर एवं यूजर चार्ज लेने का आग्रह किया है यदि जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं होती है तो नगर वासियों और उन गरीब प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों तथा फुटकर व्यापारियों को साथ लेकर कांग्रेस पार्षद दल एवं कांग्रेस पार्टी महापौर जी का एवं निगम कार्यालय का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महापौर जी एवं निगम प्रशासन की होगी।

अल्पदृष्टि बाधित बच्चे अब पढ़ सकेंगे पुस्तक, किया गया चश्मा का वितरण

कांकेर। -उत्तर बस्तर कांकेर 17 फरवरी 2026 कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देशानुसार एवं जिला शिक्षा अधिकारी रमेश कुमार निषाद के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न शालाओं में अध्ययनरत 442 अल्पदृष्टि बाधित बच्चों को चश्मा वितरण किया गया। इन सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर कार्यरत बी.आर.पी. व स्पेशल एजुकेटर के सहयोग से आंकलन शिविर के माध्यम से बच्चों का आँखों का जांच कराकर बच्चों को चश्मा वितरण किया गया। अब ये दिव्यांग बच्चे भी आसानी से पुस्तक पढ़ व लिख सकेंगे तथा अपना दैनिक जीवन के क्रियाकलाप आसानी से कर सकेंगें। चश्मा वितरण हेतु बच्चों के चयन के लिए जिले के सभी विकासखण्ड मुख्यालय में आंकलन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बच्चों का चिन्हांकन कर विशेषज्ञ डाक्टरों के द्वारा आंखो की जांच किया जाकर चश्मा का नम्बर लिया गया। ऐसे बच्चे जिनके आंखों की जांच नहीं हो पाया, ऐसे अल्पदृष्टि बच्चों का जिला चिकित्सालय में जांच कराया गया तथा सभी पात्र बच्चों के लिए जिला प्रशासन व समग्र शिक्षा के माध्यम से चश्मा उपलब्ध कराया गया। चश्मा पाकर खुशी जाहिर करते हुए भानुप्रतापपुर विकासखण्ड के कक्षा 10वीं में अध्ययनरत छात्रा कु. सोनिका भण्डारी ने बताया कि मुझे पुस्तक पढ़ने-लिखने में बहुत परेशानी होती थी, अब चश्मा मिलने पर मैं आसानी से पुस्तक पढ़ व आसानी से लिख सकती हूँ, अभी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह छात्रा कु. कंचन धुरव, कु. संगीता नरेटी, कु. शिखा चौहान और भूपेन्द्र कठेले ने बताया कि अब चश्मा मिलने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है।

अपनी मांगों को लेकर प्लेसमेंट कर्मचारियों ने सीएमओ से की मुलाकात, पालिका इतिहास में पहली बार होगी त्रिपक्षीय बैठक

कांकेर। कांकेर नगर पालिका कांकेर के प्लेसमेंट कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) एवं पालिका अध्यक्ष से मुलाकात की। कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को विस्तार से अधिकारियों के समक्ष रखते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय कर्मचारी यूनियन, कांकेर इकाई के अध्यक्ष राकेश बिछिया एवं महासचिव दिलीप साहू ने बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि सीएमओ की उपस्थिति में नियोजक (ठेकेदार) और कर्मचारियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की जाए। उनका कहना है कि ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि समय पर उपलब्ध नहीं रहता, जिससे कर्मचारियों की समस्याएं लंबित रहती हैं और मनमानी की स्थिति बनी रहती है। नेताओं ने बताया कि कर्मचारियों को वितरित किए गए कई ईएसआई कार्ड त्रुटिपूर्ण हैं, जिन्हें सात दिवस के भीतर सुधारने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन तीन माह बीतने के बाद भी सुधार नहीं किया गया। वहीं वेतन भुगतान भी निर्धारित तिथि पर नहीं हो रहा है। 15 से 20 दिन की देरी से वेतन मिलने के कारण कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।यूनियन की मांग पर सीएमओ ने ठेकेदार को कांकेर बुलाकर त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। यह बैठक नगर पालिका के इतिहास में पहली बार सीएमओ, ठेकेदार एवं कर्मचारी प्रतिनिधियों की संयुक्त उपस्थिति में आयोजित की जाएगी, जिसे कर्मचारी एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहल मान रहे हैं। बैठक में प्रत्येक माह वेतन पर्ची वितरण, निर्धारित तिथि पर वेतन भुगतान तथा अन्य लंबित मांगों पर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही होली पर्व से पूर्व फरवरी माह का वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने पर भी सहमति बनी है। सफाई एवं बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की मांग पर सीएमओ ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक सुरक्षा सामग्री वितरित करने के निर्देश दिए। प्रतिनिधिमंडल में भाव सिंह कश्यप, द्वारका कोसरिया, कामेंद्र गिरी, दिलीप साहू।

समय-सीमा में काम पूरा करें गुणवत्ता से समझौता नहींः कलेक्टर

बीजापुर। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में कलेक्टर संबित मिश्रा ने जिले में चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने स्वीकृत निर्माण कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर और बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।

अधोसंरचना कार्यों पर फोकस-बैठक में नियद नेल्लानार क्षेत्रों में जारी अधोसंरचना निर्माण की स्थिति पर विशेष चर्चा हुई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि कार्यों में तेजी लाई जाए और नियमित मॉनिटरिंग की जाए, ताकि परियोजनाएं समय पर पूरी हों। सैचुरेशन शिविरों की उपलब्धियों की भी समीक्षा की गई और निर्देश दिए गए कि योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक पहुंचे।

दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया आसान करने के निर्देश-कलेक्टर ने आधार पंजीयन में तेजी लाने पर जोर देते हुए जन्म प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, राशन कार्ड समेत जरूरी दस्तावेज लोगों को सरल प्रक्रिया से उपलब्ध कराने को कहा। खासतौर पर नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित व्यक्तियों को समय पर दस्तावेज देने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए।

दुर्गेश जोशी जिला कार्यसमिति सदस्य नियुक्त , क्षेत्र में हर्ष की लहर

कोण्डागांव। दुर्गेश जोशी को भारतीय जनता पार्टी जिला कोंडागांव की जिला कार्यसमिति में सदस्य नियुक्त किए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में हर्ष का माहौल है। उनकी नियुक्ति को संगठन के प्रति उनके समर्पण, सक्रियता और निरंतर जनसेवा का परिणाम माना जा रहा है। पार्टी पदाधिकारियों ने विश्वास जताया है कि जोशी के अनुभव एवं संगठनात्मक क्षमता से जिले में पार्टी को और अधिक मजबूती मिलेगी। लंबे समय से संगठन से जुड़े जोशी विभिन्न सामाजिक एवं जनहितकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। नियुक्ति की घोषणा के बाद समर्थकों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं तथा उनके उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की। इस अवसर पर श्री जोशी ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे संगठन द्वारा सौंपे गए दायित्व का पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे तथा जिले में पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

बस्तर में बाल संरक्षण की अनूठी मिसाल

कलेक्टर आकाश छिकारा ने सराहनीय कदम उठाए हैं बस्तर में बच्चों 5 को सुरक्षित भविष्य के लिए पोस्टर परिवारो को सौंपा

बच्चों को सुरक्षित भविष्य के लिए फोस्टर परिवारों को सौंपा

जगदलपुर । जगदलपुर में बाल संरक्षण और बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में जिला प्रशासन ने एक अत्यंत संवेदनशील और सराहनीय कदम उठाया है। कलेक्टर आकाश छिकारा द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग की फोस्टर केयर योजना के अंतर्गत दो जागरूक परिवारों को कुल 5 बच्चों की जिम्मेदारी विधिवत सौंपी गई। जिला बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार पूर्ण की गई इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को एक सुरक्षित और स्नेहपूर्ण पारीवारिक वातावरण उपलब्ध कराना है, जिन्हें विशेष देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर कलेक्टर - छिकारा ने फोस्टर परिवारों से सीधा संवाद करते हुए बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, उत्तम शिक्षा और उनके समग्र पालन-पोषण को लेकर आवश्यक समझाइश देते हुए कहा कि प्रशासन बाल संरक्षण तंत्र को निरंतर सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इन परिवारों को भविष्य में भी हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। बस्तर के इन दो परिवारों द्वारा 5 बच्चों के संरक्षण की जिम्मेदारी उठाना न केवल एक मानवीय पहल है, बल्कि यह ग्राम स्तर पर सामुदायिक भागीदारी और संवेदनशील नेतृत्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी पेश करता है। इस पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने में प्रशासनिक तालमेल और तकनीकी विशेषज्ञता का विशेष योगदान रहा। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष नरेन्द्र पाणिग्राही, सदस्य श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, श्रीमती धनेश्वरी वर्मा, सन्तोष जोशी, रामकृष्ण ठाकुर सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज सिन्हा और जिला बाल संरक्षण अधिकारी डॉ. विजय शंकर शर्मा की टीम ने बच्चों के सर्वोत्तम हित को सर्वोपरि रखते हुए इस कार्य को सुनिश्चित किया। वहीं तकनीकी सहयोगी के रूप में सीईएसी-यूनिसेफ के जिला अधिकारी रमेश कुमार दास ने फोस्टर केयर प्रक्रिया, क्षमता निर्माण और पारदर्शी दस्तावेजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामुदायिक जागरूकता और प्रशासनिक तत्परता के समन्वय से शुरू हुई यह पहल न केवल इन पाँच बच्चों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी, बल्कि समाज में बाल अधिकारों के प्रति एक नई संवेदनशीलता भी जागृत करेगी। यह कदम भविष्य में जिले के भीतर बाल संरक्षण की एक सुदृढ़ और व्यवस्थित प्रणाली स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चीफ जस्टिस की माता जी श्रीमती कुसुम सिन्हा को दी श्रद्धांजलि

बिलासपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा की पूज्य माता स्वर्गीय श्रीमती कुसुम सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीमती सिन्हा का 15 फरवरी को निधन हो गया था। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर के बोदरी स्थित मुख्य न्यायाधीश निवास में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर श्रीमती सिन्हा के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया और कहा कि माता जी का स्नेह, संस्कार और त्याग जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। श्रीमती कुसुम सिन्हा का सरल, स्नेहमयी और अनुपम स्वभाव सदैव स्मरणीय रहेगा। इस अवसर पर केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री एवं सांसद श्री तोखन साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, पूर्व राज्यपाल श्री रमेश बैस, विधायक श्री सुशांत शुक्ला ने भी श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त की। कार्यक्रम में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीगण, अधिवक्तागण, महाधिवक्ता कार्यालय के अधिकारी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक,संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

किसानों से उर्वरक का अग्रिम उठाव करने की अपील

बिलासपुर। खरीफ वर्ष 2026 की खेती को सुचारू एवं समयबद्ध रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम उठाव की प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू हो गई है जो 31 मई 2026 तक चलेगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य खरीफ मौसम के दौरान किसानों को उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना, संभावित कमी से बचाव करना तथा वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखना है। विभाग द्वारा इस वर्ष कुल 22 हजार 500 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 10 हजार 500 मीट्रिक टन यूरिया, 5 हजार 700 मीट्रिक टन डीएपी, 3 हजार 800 मीट्रिक टन एनपीके, 500 मीट्रिक टन एमओपी तथा 2 हजार मीट्रिक टन एसएसपी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अग्रिम उठाव कार्यक्रम के अंतर्गत उर्वरकों का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। शासन द्वारा किसानों को राहत देते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 1 फरवरी से 31 मई 2026 तक अग्रिम रूप से उठाए गए उर्वरकों पर किसानों से किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा और वे बिना अतिरिक्त वित्तीय बोझ के समय पर आवश्यक उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे। कृषि विभाग ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे खरीफ मौसम की तैयारी को ध्यान में रखते हुए अपनी नजदीकी सहकारी समिति से समय रहते उर्वरकों का अग्रिम उठाव कर लें, ताकि सीजन के दौरान संभावित कमी, भीड़, वितरण अव्यवस्था और विलंब जैसी समस्याओं से बचा जा सके।

जिले में पशुकल्याण पखवाड़ा का सफल आयोजन 926 पशुपालकों ने लिया शिविर का लाभ

बिलासपुर। जिले में पशुपालन विभाग द्वारा जिला स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय पशुपालन एवं पशुकल्याण जागरूकता पखवाड़ा का सफल आयोजन किया गया। पखवाड़े के अंतर्गत विकासखण्डों और गांवों में शिविर के माध्यम से पशुपालकों को निःशुल्क सेवाओं का लाभ मिला तथा पशुधन संरक्षण और उत्पादन बढ़ाने संबंधी जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान 926 पशुपालकों के 3 हजार 257 पशुओं का पंजीयन किया गया। इनमें से 528 पशुओं का उपचार, 1 हजार 453 पशुओं को कृमिनाशक दवापान कराया गया। 1 हजार 118 पशुओं को औषधि, 3 हजार 126 पशुओं का टीकाकरण, 51 पशुओं का बधियाकरण और पशुओं के विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जांच किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और आधुनिक पशुपालन तकनीकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। जागरूकता पखवाड़े के दौरान कृषक संगोष्ठी एवं स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।

संरक्षा के सजग प्रहरियों को महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने किया सम्मानित

बिलासपुर। रेल परिचालन में संरक्षा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है । सजगता एवं बेहतर संरक्षा कार्य में सहभागिता निभाने वाले रेल संरक्षा के सजग प्रहरी कर्मचारियों का सम्मान महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा हर माह आयोजित संरक्षा बैठक के दौरान किया जाता है । इसी कड़ी में आज दिनांक 18 फरवरी, 2026 को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कार्यरत संरक्षा कोटि के 07 कर्मचारियो को उनके उत्कृष्ट एवं सराहनीय संरक्षा संबंधी कार्य निष्पादन के लिए महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश के द्वारा सम्मानित किया गया । बिलासपुर रेल मण्डल के ट्रैक मैंटेनर-IV/ बाराद्वार श्री हिमांशु ने दिनांक 11 जनवरी, 2026 को अपने ड्यूटी के दौरान सक्ती - बाराद्वार सेक्शन के बीच रात्रि में ट्रैक पैट्रोलिंग के दौरान अप लाइन में किलो मीटर नं.- 645/17 पर रेल फ्रेक्चर देखा और तत्काल इसकी सूचना सर्वसंबंधित को दिया जिसके उपरांत आवश्यक कार्यवाही कर ट्रैक को ठीक किया गया । इस प्रकार श्री हिमांशु की सजगता एवं सतर्कता से ट्रेन परिचालन में संरक्षा सुनिश्चित हुई । बिलासपुर रेल मण्डल के ट्रैक मैंटेनर-IV/नैला श्री चन्दन कुमार ने दिनांक 29 जनवरी, 2026 को अपने ड्यूटी के दौरान माल गाड़ी के इंजन से तीसरा वैगन में हॉट एक्सल देखा, तत्काल इसकी सूचना सर्वसंबंधित को दिया, जिसके

उपरांत आवश्यक कार्यवाही कर गाड़ी को सुरक्षित रवाना किया गया । इस प्रकार श्री चन्दन कुमार की सजगता एवं सतर्कता से ट्रेन परिचालन में संरक्षा सुनिश्चित हुई । रायपुर रेल मण्डल के लोको चालक (गुड्स)/भाटापारा श्री खिलेश्वर कुमार ने दिनांक 28 जनवरी, 2026 को अपने ड्यूटी के दौरान निरीक्षण करते समय लोको इंजिन के इंटरमीडियट कैब बफर हाउसिंग मे दरारें एवं टूटे हुए हिस्से को देख कर तत्काल इसकी सूचना सर्वसंबंधित को दिया । जिसके उपरांत आवश्यक कार्यवाही कर गाड़ी का सुरक्षित संचालन किया गया । इस प्रकार श्री खिलेश्वर कुमार की सजगता एवं सतर्कता से ट्रेन परिचालन में संरक्षा सुनिश्चित हुई । नागपुर रेल मण्डल के की-मैन / चांदाफोर्ट, श्री अश्विन भास्कर गोवर्धन ने दिनांक 20 दिसम्बर, 2025 को अपने ड्यूटी के दौरान रजोली-मूलमरोड़ा सेक्शन में ड्यूटी के दौरान किलो मीटर नं.- 1185/20-21 में वेल्ड फ्रेक्चर देखा और तत्काल इसकी सूचना सर्वसंबंधित को दिया जिसके उपरांत आवश्यक कार्यवाही कर ट्रैक को ठीक किया गया । इस प्रकार श्री अश्विन भास्कर गोवर्धन की सजगता एवं सतर्कता से ट्रेन परिचालन में संरक्षा सुनिश्चित हुई । नागपुर रेल मण्डल के की-मैन/चंदाफोर्ट श्री विश्राम साहु ने दिनांक 21 दिसम्बर,2025 को अपने ड्यूटी के आलेवाही-सिंदेवाही सेक्शन में ड्यूटी के दौरान किलो मीटर नंबर 1163/2-3 में वेल्ड फ्रेक्चर देखा और तत्काल इसकी सूचना सर्वसंबंधित को दिया जिसके उपरांत आवश्यक कार्यवाही कर ट्रैक को ठीक किया गया । इस प्रकार श्री विश्राम साहु की सजगता एवं सतर्कता से ट्रेन परिचालन में संरक्षा सुनिश्चित हुई ।नागपुर रेल मण्डल के ट्रैक मैंटेनर-III/ ग्वारिघाट श्री मनोज कुमार यादव ने दिनांक 23/24 नवम्बर , 2025 को अपने ड्यूटी के दौरान घंसौरङ्कबिनेकी सेक्शन में ड्यूटी के दौरान किलो मीटर 1155/11J-12J में रेल फ्रेक्चर देखा और तत्काल इसकी सूचना सर्वसंबंधित को दिया जिसके उपरांत आवश्यक कार्यवाही कर ट्रैक को ठीक किया गया । इस प्रकार श्री मनोज कुमार यादव की सजगता एवं सतर्कता से ट्रेन परिचालन में संरक्षा सुनिश्चित हुई । नागपुर रेल मण्डल के ट्रैक मैंटेनर-III/आमगांव श्री उत्तम कुमार ने दिनांक 28/29 नवम्बर, 2025 को अपने ड्यूटी के दौरान सालेकसा धानौली सेक्शन में ड्यूटी के दौरान कि. मी. 969/15-17 में वेल्ड फ्रेक्चर देखा और तत्काल इसकी सूचना सर्वसंबंधित को दिया जिसके उपरांत आवश्यक कार्यवाही कर ट्रैक को ठीक किया गया । इस प्रकार श्री उत्तम कुमार की सजगता एवं सतर्कता से ट्रेन परिचालन में संरक्षा सुनिश्चित हुई । इन संरक्षा कोटि के कर्मचारियों को सम्मानित किए जाने के अवसर पर प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी, प्रधान मुख्य इंजीनियर अन्य विभागाध्यक्ष सहित अधिकारीगण उपस्थित थे ।

सीएसआर के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सराहनीय योगदान रहा..

■ दिव्यांग महिलाओं को मिली स्वच्छता सुविधा

बिलासपुर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रीजनल शाखा बिलासपुर द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत महिला दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। बैंक ने समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित शासकीय आश्रयदत्त कर्मशाला, तिफरा, बिलासपुर में 100 सेनेटरी पैड एवं 01 डिस्पेंसिंग मशीन उपलब्ध कराई। इसी क्रम में मानसिक रूप से पुनर्वासित महिलाओं के लिए संचालित हाफ वे होम, कोनी में 200 सेनेटरी पैड एवं 02 डिस्पेंसिंग मशीनें प्रदान की गईं। इन संसाधनों से संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहीं दिव्यांग महिलाओं को स्वच्छता

संबंधी सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर एसबीआई के एचआर मैनेजर श्री हर्ष तिवारी ने उपस्थित महिलाओं एवं संस्था प्रभारियों को मशीन के उपयोग और सेनेटरी पैड के सुरक्षित व स्वच्छ इस्तेमाल की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समाज के वंचित वर्गों, विशेषकर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। यह पहल महिला स्वच्छता, गरिमा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।कार्यक्रम में संयुक्त संचालक श्री टी.पी. भावे, उपनियंत्रक श्रीमती वीना कमलेश, सहायक सांख्यिकी अधिकारी श्री प्रशांत मोकासे, आश्रयदत्त कर्मशाला की प्रभारी अधीक्षक सुश्री वीना दीक्षित एवं हाफ वे होम कोनी के व्यवस्थापक श्री प्रमोद शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

ई-ऑफिस के संबंध में अधिकारी कर्मचारियों को मिला प्रशिक्षण...

बिलासपुर। शासकीय कार्यों में पारदर्शिता, त्वरित निस्तारण एवं कार्यालयीन प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यम से सुगम बनाने के उद्देश्य से आज प्रार्थना भवन सभाकक्ष में ई-ऑफिस संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण में ई-ऑफिस प्रणाली के संचालन, ऑनलाइन फाइल मूवमेंट, ई-नोटशीट तैयार करने, पत्राचार अपलोड करने तथा डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन दर्ज करने तथा अवकाश आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षकों ने बताया कि इन

व्यवस्थाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी तथा लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी आएगी। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को व्यावहारिक अभ्यास भी कराया गया, जिससे वे अपने कार्यालयों में इन प्रणालियों का सुचारू उपयोग कर सकें।

सरकंड़ा मुक्तिधाम उपकेन्द्र में अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापित,6 हजार उपभोक्ता होंगे लाभान्वित:कार्यपालक निदेशक एके अम्बस्थ

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि तथा आगामी ग्रीष्मऋतु को दृष्टिगत रखते हुये जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्यमान उपकेन्द्रों में स्थापित पॉवर ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। इसी क्रम में सरकंडा मुक्तिधाम उपकेन्द्र में विद्यमान 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र में लगभग राशि 69 लाख रूपये की लागत से 3.15 एम.व्ही.ए. क्षमता का अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। अब नगर संभाग-दो, (नेहरू नगर) के अंतर्गत सरकंडा मुक्तिधाम उपकेन्द्र की क्षमता 5 एम.व्ही.ए. से बढ़कर 8.15 एम.व्ही.ए. हो गयी है। विद्युत कंपनी के विशेष प्रयासों से विद्युत विकास के लिए स्वीकृत इस कार्य से उपकेन्द्र के परिधि में आने वाले

उपभोक्ताओं को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। नगर संभाग-दो (नेहरू नगर) के कार्यपालन अभियंता श्री बी.बी. नेताम ने बताया कि उपकेन्द्र में 3.15 एम.व्ही.ए. के अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर के उर्जीकरण से सीपत चौक, वीआईपी कालोनी, बुधिया काम्पलेक्स, चटर्जी गली, बंगाली पारा, जबड़ापारा, शिव हनुमान मंदिर, जैन मंदिर एवं महामाया चौक के लगभग 6 हजार उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण तथा निर्बाध विद्युत की आपूर्ति होगी। बिलासपुर क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक ए.के. अम्बस्थ ने स्वीच दबाकर नये ट्रांसफार्मर के माध्यम से शहर में विद्युत सप्लाई प्रारंभ की तथा अपने उद्बोधन में कहा कि विद्युत विभाग उपभोक्ताओं की सुविधाओं में निरंतर वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कडी में आज इस उपकेन्द्र में नवीन ट्रांसफार्मर को उर्जीकृत किया गया है, जिसका लाभ इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को मिलेगा। उन्होने इस कार्य को सफलतापूर्वक किये जाने पर नगर वृत्त बिलासपुर के अधीक्षण अभियंता पी.श्रीनिवास राजू, कार्यपालन अभियंता मिलिंद पाण्डेय, सी.पी.गढ़ेवाल सहायक अभियंता श्रीमती संचारी सिंह, श्रीमती छाया जीनस, बी.बी.जायसवाल, संतोष देवांगन कनिष्ठ अभियंता कु. कल्याणी वर्मा, प्रदीप साहू एवं एस.टी.एम. व एच.टी. (मेंटेनेंस) टीम की सराहना की है।

लोकतंत्र की मज़बूती के लिए युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण - सतीश प्रकाश सिंह

बिलासपुर। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार जिले के युवाओं को निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने हेतु दिनांक 18 फरवरी 2026 को सहायक जिला स्वीप नोडल अधिकारी सतीश प्रकाश सिंह की उपस्थिति में स्व प्यारे लाल कंवर शासकीय महाविद्यालय भैसमा में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (श्वस्ष्ट) का गठन किया गया। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रंगोली प्रतियोगिता में महाविद्यालय की छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। छात्राओं ने आकर्षक रंगोली बनाकर इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (श्वस्ष्ट), विशेष गहन पुनरीक्षण (स्ढ्ढक्र) और मतदान के महत्व को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया। इस अवसर पर सहायक जिला स्वीप नोडल अधिकारी सतीश प्रकाश सिंह ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए एस.आई.आर.का महत्व बताया तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक युवा को एक जागरूक मतदाता के रूप में अपने मतदान केंद्र में अपना नाम पंजीकृत कराने के लिए प्रेरित किये। उन्होंने लोकतंत्र की मजबूती के लिए युवाओं के योगदान को महत्वपूर्ण बताया । सहायक जिला स्वीप नोडल अधिकारी सतीश प्रकाश सिंह ने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के गठन के उद्देश्यों को विस्तार से बताया तथा युवाओं से लोकतंत्र की मज़बूती के लिए आगे आकर अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किये। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. साधना खरे ने स्वीप कार्यक्रम की गतिविधियों में महाविद्यालय द्वारा सदैव अग्रणी रूप से सहयोग किये जाने की जानकारी दी। कार्यक्रम के प्रारम्भ में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. साधना खरे एवं सहायक जिला स्वीप नोडल अधिकारी सतीश प्रकाश सिंह ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। तत्पश्चात कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत एवं मतदाता जागरूकता सम्बन्धी गीत की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में महाविद्यालय की आयोजन टीम का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्राध्यापक दीपेश कुमार के द्वारा किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. जे. एल. चौहान, सहायक प्राध्यापक जितेंद्र कँवर, डॉ. अनुराधा तिर्की महाविद्यालय स्वीप नोडल अधिकारी सहित महाविद्यालय के अन्य प्राध्यापकगण और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

स्काउटिंग को गति देने मेम्बरशिप ग्रोथ पर करें फोकस :राज्य मुख्य आयुक्त इंद्रजीत खालसा...

बिलासपुर। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के जिला संगठन आयुक्तों की समीक्षा बैठक राज्य मुख्य आयुक्त श्री इंद्रजीत सिंह खालसा की अध्यक्षता में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक में राज्य मुख्य आयुक्त ने मेम्बरशिप ग्रोथ पर जोर दिया। उन्होंने जिला संगठन आयुक्तों से ऑनलाइन यूथ मैनेजमेंट सिस्टम पर प्राथमिकता के साथ फोकस करने एवं नए शैक्षणिक सत्र में बेसिक कोर्स के लिए कार्ययोजना बनाने कहा। जिला संगठन आयुक्तों के साथ आयोजित हुई बैठक की अध्यक्षता राज्य मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने की। बैठक में विशेष रूप से राज्य कोषाध्यक्ष हेमंत देवांगन की उपस्थिति रही। जिलों के कामकाज को लेकर निर्धारित एजेंडा अनुसार वन- टू-वन समीक्षा की गई। जिला संगठन आयुक्तों ने एक-एक कर शैक्षणिक सत्र 2024- 25 एवं 2025-26 में अर्जित अंशदान की जानकारी दी। राज्य मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने शत प्रतिशत शासकीय विद्यालयों से अंशदान जमा करवाने कहा। स्वामी आत्मानन्द विद्यालयों से भी अंशदान जमा करवाने निर्देशित किया गया। अधिक से अधिक निजी विद्यालयों को कवर करने कहा गया। राज्य मुख्य आयुक्त ने जिला संगठन आयुक्तों से ऑनलाइन यूथ मैनेजमेंट सिस्टम पर प्राथमिकता के साथ फोकस करने कहा। ओवाईएमएस के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर या आईटी के जानकार लीडर्स एवं रोवर्स, रेंजर्स का सहयोग लेने कहा गया। जिलों में सक्रिय लीडर्स की जानकारी ली गई। सत्र 2024- 25 एवं 2025- 26 में

बेसिक कोर्स की स्थिति, बेसिक कोर्स पश्चात कितनी यूनिट प्रारंभ की गई इसको लेकर जिला संगठन आयुक्तों से चर्चा की गई। नए शैक्षणिक सत्र में बेसिक कोर्स के लिए कार्ययोजना बनाने कहा गया। जिला वार्षिक कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन की स्थिति, डिस्ट्रिक्ट मेम्बरशिप ग्रोथ स्ट्रेटजी तथा जिले का मेम्बरशिप ग्रोथ लक्ष्य, डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के शिविर व कार्यक्रमों में सहभागिता की स्थिति, सत्र 2024- 25 एवं 2025- 26 में जिले के आय व्यय की स्थिति पर भी चर्चा की गई। 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी तथा बालोद में आयोजित हुई प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी में सहभागिता को लेकर समीक्षा की गई। राज्य मुख्य आयुक्त इंद्रजीत खालसा ने कमजोर प्रदर्शन करने वाले कुछेक जिलों को कामकाज में सुधार लाने की हिदायत दी। श्री खालसा ने जिला संगठन आयुक्तों से कामकाज में आ रही दिक्कतों और समस्याओं की जानकारी ली और उसे दूर करने आश्वस्त किया। जिला संगठन आयुक्तों की सामाजिक सुरक्षा को और बेहतर करने समिति गठन करने की बात कही गई। राज्य मुख्य आयुक्त ने कहा कि टीम वर्क के साथ स्काउटिंग को गुणवत्तापूर्ण तरीके से गति देना है और देश में छतीसगढ़ की एक क्रियाशील छवि बनानी है। बैठक का संचालन प्रभारी राज्य सचिव सरिता पाण्डेय ने किया।

घर के मुख्य द्वार पर गणेश प्रतिमा रखते समय न करें ये गलतियां

वैसे तो वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर भगवान श्रीगणेश की प्रतिमा स्थापित करना शुभ माना जाता है, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं और घर को बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाते हैं। यदि आप भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर नवीन गृह प्रवेश कर रहे हैं या घर में तथा घर के दरवाजे पर श्रीगणेश की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करने की सोच रहे हैं तो कुछ नियम जान लेना उचित होगा। वास्तु शास्त्र में इसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना महत्वपूर्ण है। यदि इन नियमों का पालन न किया जाए, तो यह नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यहां कुछ गलतियां दर्शाई जा रही हैं जो घर के मुख्य द्वार पर गणेश प्रतिमा रखते समय नहीं करनी चाहिए:

1. गलत दिशा:

■ वास्तु शास्त्र के अनुसार, मुख्य द्वार पर गणेश प्रतिमा लगाने के लिए उत्तर, पूर्व या ईशान (उत्तर-पूर्व) दिशा सबसे शुभ मानी जाती है।

■ दक्षिण दिशा की ओर गणेश प्रतिमा का मुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दिशा को नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। यदि मुख्य द्वार दक्षिण में है, तो प्रतिमा इस प्रकार लगाएं कि उनका मुख घर के अंदर की ओर हो।

■ पश्चिम दिशा भी मुख्य द्वार पर गणेश प्रतिमा लगाने के लिए बहुत अनुकूल नहीं मानी जाती है। यदि इस दिशा में द्वार है, तो वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित है।

2. पीठ का ध्यान न रखना:

■ यह सुनिश्चित करें कि गणेश प्रतिमा की पीठ घर के बाहर की ओर हो। उनकी पीठ घर की ओर होना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है।

■ यदि आप दो गणेश प्रतिमाएं मुख्य द्वार पर लगा रहे हैं, तो उन्हें इस प्रकार लगाएं कि दोनों की पीठ एक-दूसरे की ओर हो, न कि घर की ओर।

3. टूटी या खंडित प्रतिमा:

■ कभी भी टूटी हुई या खंडित गणेश प्रतिमा को मुख्य द्वार पर न रखें। वास्तु शास्त्र में खंडित मूर्तियों को अशुभ माना जाता है।

4. गलत मुद्रा:

■ मुख्य द्वार पर बैठी हुई मुद्रा वाली गणेश प्रतिमा लगाना शुभ माना जाता है, जो स्थिरता और शांति का प्रतीक है।

■ खड़ी मुद्रा वाली प्रतिमा को प्रवेश द्वार पर लगाने से बचें, क्योंकि यह ऊर्जा के प्रवाह को अस्थिर कर सकती है।

■ लेटी हुई मुद्रा वाली गणेश प्रतिमा घर के अंदर शयन कक्ष में लगाई जाती है, मुख्य द्वार पर नहीं।

5.सूंड़ की दिशा:

■ गणेश प्रतिमा की सूंड़ का भी वास्तु में महत्व है। घर के मुख्य द्वार के लिए बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड़ वाली प्रतिमा को अधिक शुभ माना जाता है, जो सुख और समृद्धि का प्रतीक है। दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड़ वाली प्रतिमा को सिद्धि विनायक माना जाता है और इसकी पूजा के नियम थोड़े कठिन होते हैं, इसलिए इसे घर के अंदर मंदिर में स्थापित करना अधिक उचित है।

रात में सोने से पहले कर लें ये 3 काम

आजकल ज्यादातर लोग रात में सोने से पहले अपने फोन को ही स्क्रॉल करते रहते हैं। कई बार तो ये आदत इतनी बढ़ जाती है कि 10 मिटन से कब एक-दो घंटे हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। इसका असर ना सिर्फ हमारी नींद पर पड़ता है, बल्कि मन और शरीर भी थकान महसूस करते हैं। वास्तु शास्त्र के कुछ नियमों के अनुसार अगर हम सोने से पहले कुछ अच्छी आदतों को अपना लें तो घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। इन आदतों के चलते ही जिंदगी में पॉजिटिविटी और बरकत आती है। साथ ही सही नियम का पालन करने से हमारी मन भी शांत रहने लगता है शरीर भी सही रहता है। आज जानेंगे वास्तु शास्त्र के उन तीन आसान से नियमों के बारे में जो हमें सोने से पहले जरूर करने चाहिए ताकि हमारी जिंदगी में सुख-शांति बनी रहें और घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहें।

1 वास्तु शास्त्र के नियम के हिसाब से सोने से पहले ड्रॉवर के पास हमें तांबे का एक कलश रखना चाहिए,क्योंकि इससे मन शांत रहता है। साथ ही नींद भी अच्छी आती है। ये कलश साइज में छोटा या बड़ा हो सकता है। इसमें साफ पानी भरकर रख दें और फिर सो जाएं। नियम के अनुसार ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। जिन लोगों को नींद से जुड़ी दिक्कत होती है, उन्हें ये उपाय जरूर करना चाहिए। सुबह उठने के बाद इस कलश के पानी को अपने गार्डेन एरिया में डाल देना चाहिए।

2 कई लोग किचन में जूठे बर्तन छोड़ देते हैं कि अगली सुबह इन्हें साफ कर लिया जाएगा। ऐसा करना गलत है। अगर सोने से पहले किचन में जूठे बर्तन छोड़े जाते हैं तो इससे घर में नेगेटिविटी आती और घर का वास्तु भी खराब होता है। ऐसे में सोने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सारे बर्तन साफ कर लिए जाए। इसके अलावा सोने से पहले किचन को भी साफ करना शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से घर में धन-धान्य की कोई भी कमी नहीं होती है और बरकत भी आती है।

3 सबसे जरूरी बात है कि आप किस दिशा की ओर सो रहे हैं। वास्तु शास्त्र में दिशा का बहुत ही महत्व होता है। ऐसे में सही दिशा में सोना जरूरी है। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर सोने से हर किसी को बचना चाहिए। जब भी उत्तर दिशा में सोया जाएगा तो पैर दक्षिण दिशा की ओर होंगे, जोकि अच्छा नहीं माना जाता है। ये भी सुनिश्चित कर लें कि आपका बेड उत्तर-पूर्व दिशा की ओर ना हो।

हेयरस्टाइल को बनाते समय इस ट्रिक को जरूर फॉलो करें

काफी सारी लेडीज जिनकी एज 30 के ऊपर होने लगती है। अक्सर उनका लुक अपनी एज से ज्यादा नजर आने लगता है। दरअसल, आपके एज वाले लुक का कारण कई बार हेयरस्टाइल होती है। अगर आप यूथफुल डिजाइन वाले हेयरस्टाइल बनाती हैं तो इंस्टेंटली अपनी एज से कम उमर की नजर आएंगी। और काफी सारे मेकअप आर्टिस्ट इस बारे में नहीं बताते। लेकिन फेस पर लिफ्टेड लुक चाहिए तो हेयरस्टाइल बनाते समय बस इस सिंपल ट्रिक को ट्राई करें।

हेयरस्टाइल बनाने का ये तरीका

अगर आप थोड़ा गर्ली लुक क्रिएट करना चाहती हैं। या फेस पर यूथफुल इफेक्ट चाहती हैं तो हेयरस्टाइल को इग्नोर ना करें। थोड़ा गर्ली लुक क्रिएट करने वाली हेयरस्टाइल आपको इंस्टेंट तरीके से एज से कम दिखाने में मदद करेगी।

यंग लुक के लिए हेयरस्टाइल सीक्रेट

हेयरस्टाइल से खुद को यंग दिखाने का सीक्रेट कंटेंट क्रिएटर फैजा शोएब ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। फैजा ने बताया है कि कैसे कानों के पास साइड वाले हेयर को ऊपर की तरफ हल्का पुल करके पिन से सेट कर लिया जाए और फिर किसी भी तरह ही हेयरस्टाइल को क्रिएट करें। तो ऐसा करने से चिक बोंस के साथ साइड से फेस ना केवल ज्यादा अपलिफ्ट नजर आता है। बल्कि इंस्टेंटली आप उम्र से कम भी नजर आने लगती है। खासतौर पर जिन लेडीज का फेस हैवी है उन्हें ये खींचकर हेयरस्टाइल बनाने की ट्रिक को जरूर फॉलो करना चाहिए। इससे फेस ना केवल थोड़ा स्लिम दिखेगा बल्कि यंग और अपलिफ्ट नजर आएगा।

बनाएं ये हेयरस्टाइल

फ्रंट पार्टीशन हेयरस्टाइल बनाना चाहती हैं तो बालों को फ्रंट से दो सेक्शन में कर लें। फिर वन साइड के बालों में टेंपल एरिया के बालों को कंघी करके निकालें और इन्हें पीछे की तरफ ले जाकर पिन से सेट कर लें। या फिर दोनों तरफ से टेंपल एरिया के बालों को खींचकर पीछे की ओर ले जाकर रबरबैंड से फिक्स कर लें। फिर फ्रंट के बालों को कंघी से सेट करके उन्हें पीछे की तरफ पिनअप करें या फिर साइड पार्टीशन करके छोड़ दें।

नाइट स्किन केयर का आसान फॉर्मूला

हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा साफ, चमकदार और हेल्दी दिखे, लेकिन प्रदूषण, धूल-मिट्टी और बिजी लाइफस्टाइल स्किन की चमक छीन लेते हैं। ऐसे में लोग महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, रात का समय स्किन रिपेयर के लिए सबसे बेहतर होता है और कुछ घरेलू चीजों का नियमित इस्तेमाल चेहरे की रंगत निखार सकता है।

रात का समय क्यों है स्किन के लिए खास

दिनभर स्किन धूप, धूल और प्रदूषण के संपर्क में रहती है। रात के समय शरीर और त्वचा खुद को रिपेयर करती है। इसी वजह से अगर सोने से पहले सही चीजें लगाई जाएं, तो उनका असर ज्यादा बेहतर दिखाई देता है।

1. कच्चा दूध: नेचुरल क्लींजर और ग्लो बूस्टर

कच्चा दूध लंबे समय से स्किन केयर में इस्तेमाल होता आ रहा है। इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को साफ करने और निखारने में मदद करता है। इस्तेमाल के लिए 1-2 चम्मच कच्चा दूध लें, रुई की मदद से चेहरे पर लगाएं और सूखने दें। चाहें तो इसे दोबारा लगाकर 20 मिनट बाद ठंडे पानी से धो सकते हैं या रातभर छोड़ सकते हैं। इससे चेहरे की गंदगी निकलती है और टैनिंग कम होती है।

2. बादाम का तेल: ड्रायनेस और डार्क सर्कल्स का समाधान

अगर चेहरा रूखा लगता है या आंखों के नीचे काले घेरे हैं, तो बादाम का तेल फायदेमंद हो सकता है। इसमें विटामिन-ई भरपूर मात्रा में होता है, जो त्वचा को पोषण देता है। रात को 2-3 बूंद बादाम का तेल चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से थपथपाएं और आंखों के नीचे हल्की मसाज करें। यह स्किन में नमी लाकर नेचुरल ग्लो देता है।

3. एलोवेरा जेल: हर स्किन टाइप के लिए फायदेमंद

एलोवेरा जेल को स्किन के लिए फायदेमंद माना जाता है। यह त्वचा को ठंडक, नमी और राहत देता है। सोने से पहले चेहरा धोकर फ्रेश एलोवेरा जेल लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। इसे रातभर लगा रहने दें। इससे कील-मुंहासों के दाग हल्के हो सकते हैं और त्वचा मुलायम बनती है।

टमाटर से बना हलवा

टमाटर का हलवा न सिर्फ टेस्ट में बेहतरीन होता है, बल्कि पोषण से भरपूर भी होता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक, यह स्वीट डिश सभी को खूब पसंद आती है। अगर आप वीकेंड पर किचन में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो टमाटर का हलवा एक परफेक्ट ऑप्शन है। आइए जानते हैं इसे

लौकी और गाजर का हलवा आपने कई बार खाया होगा, लेकिन अगर हर बार वही स्वाद खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ हटकर ट्राई कीजिए। टमाटर से बना हलवा सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार खाने के बाद हर कोई इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। आमतौर पर टमाटर का इस्तेमाल स जी, सलाद या चटनी में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे स्वादिष्ट मीठा भी बनाया जा सकता है?

बनाने की आसान रेसिपी।

टमाटर का हलवा बनाने की सामग्री

टमाटर - 10 से 12,चीनी - 2 कप,घी - आधा कप,काजू - 20,किशमिश - 2 चम्मच,हरी इलायची - 6,लौंग - 4,तुलसी के पत्ते - 1/4 कप,गुलाब की पंखुड़ियां - 1/4 कप

टमाटर का हलवा बनाने की विधि

स्टेप 1 - सबसे पहले टमाटरों को अच्छी तरह धो लें। ऊपर से डंठल निकालें और नीचे हल्का सा क्रॉस कट लगाएं। अब इन्हें उबलते पानी में 2-3 मिनट के लिए डाल दें। जब छिलका ढीला हो जाए, तो टमाटर निकालकर छील लें और बीज अलग कर दें। गूदा और रस एक तरफ रख दें।

स्टेप 2 - हरी इलायची को 1 चम्मच चीनी के साथ कूटकर बारीक पाउडर बना लें। कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालकर काजू और किशमिश को हल्का सुनहरा होने तक भून लें और अलग निकाल लें। तुलसी के पत्तों और गुलाब की पंखुड़ियों को धोकर बारीक काट लें।

स्टेप 3 - एक बर्तन में आधी चीनी और आधा कप पानी डालकर हल्की चाशनी तैयार करें। दूसरी ओर कढ़ाई में घी गरम करें, उसमें लौंग डालें और फिर टमाटर का गूदा डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब टमाटर का पानी सूख जाए और मिश्रण गाढ़ा होने लगे, तब अगला स्टेप करें।

स्टेप 4 - अब आंच थोड़ा तेज करें और तैयार चाशनी को धीरे-धीरे टमाटर के मिश्रण में मिलाएं। लगातार चलाते रहें। जब हलवा कढ़ाई छोड़ने लगे और अच्छी खुशबू आने लगे, तो समझ लें कि हलवा तैयार है।

स्टेप 5 - अंत में इलायची पाउडर, तुलसी के पत्ते और गुलाब की पंखुड़ियां डालें। ऊपर से भुने हुए काजू और किशमिश डालकर अच्छी तरह मिलाएं। गरमागरम टमाटर का हलवा परोसें।

छाती में दुर्लभ सिस्ट से पीड़ित मरीज की रोबोटिक सर्जरी

परेल स्थित ग्लेनेईगल्स अस्पताल में 43 वर्षीय मरीज राहुल जगताप का अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी द्वारा सफल इलाज किया गया। मरीज पिछले दो महीनों से छाती में जलन, भारीपन और दबाव की समस्या से परेशान थे। विस्तृत जांच में छाती के अंदर एक दुर्लभ इसोफेगल डुप्लिकेशन सिस्ट पाई गई, जो भोजन नली और हृदय पर दबाव डाल रही थी। सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एवं मिनिमल एक्सेस सर्जरी डायरेक्टर डॉ. प्रशांत राव के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने पारंपरिक ओपन सर्जरी के बजाय रोबोटिक, मिनिमली इनवेसिव सर्जरी का विकल्प चुना। जनवरी 2026 में की गई सर्जरी सफल रही और सिस्ट को सुरक्षित रूप से निकाल दिया गया। सर्जरी के चौथे दिन मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल के सीईओ डॉ. बिपीन चेवले ने बताया कि इस जटिल प्रक्रिया में उन्नत रोबोटिक तकनीक का उपयोग किया गया, जिससे सर्जरी अधिक सटीक, सुरक्षित और कम दर्द वाली रही। इस तकनीक से मरीज तेजी से स्वस्थ होकर सामान्य जीवन में लौट सकता है। मरीज राहुल जगताप ने अस्पताल की टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समय पर सही निदान और आधुनिक उपचार से उन्हें नई जिंदगी मिली है।

न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इलाज

ऑनलाइन स्वास्थ्य जानकारी के आधार पर खुद को गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी से ग्रस्त मान बैठी 32 वर्षीय एक महिला को आखिरकार विशेषज्ञ परामर्श के बाद राहत मिली। लगातार थकान को मल्टीपल स्क्लेरोसिस (एमएस) समझ लेने के कारण वह मानसिक तनाव में थी और अपने महत्वपूर्ण जीवन निर्णय तक टाल चुकी थी। महिला ने इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी पढ़ने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। हालांकि उसके पास केवल एक ही लक्षण था — लगातार थकान। न दृष्टि संबंधी समस्या, न हाथ-पैरों में कमजोरी, न संवेदनशीलता में बदलाव और न ही किसी न्यूरोलॉजिकल अटैक का इतिहास था। इसके बावजूद गंभीर बीमारी के डर ने उस पर गहरा मानसिक प्रभाव डाला और उसने अपनी नियोजित आईवीएफ प्रक्रिया भी स्थगित कर दी।

मामला तब स्पष्ट हुआ जब उसने डॉ. शीतल गोयल, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, वॉकहार्ट अस्पताल - मुंबई सेंट्रल, से परामर्श लिया। डॉक्टर ने बताया कि जब उनसे पूछा गया कि एमएस का निदान किसने किया, तो महिला ने जवाब दिया — "ChatGPT।"अस्पताल की ओपीडी में विस्तृत क्लिनिकल जांच की गई। विशेषज्ञ मूल्यांकन में पाया गया कि मरीज के लक्षण मल्टीपल स्क्लेरोसिस के स्थापित निदान मानकों से मेल नहीं खाते। अंततः डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि महिला को एमएस नहीं, बल्कि तनाव से जुड़ी थकान और चिंता की समस्या है। डॉ. गोयल ने कहा, "उस दिन हमारा काम किसी बीमारी का इलाज करना नहीं, बल्कि एक गलत धारणा को दूर करना और मरीज को अनावश्यक भय से मुक्त करना था।"एमएस की आशंका समाप्त होने के बाद महिला ने राहत महसूस की और अपनी आईवीएफ योजना को फिर से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।विशेषज्ञों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन वे चिकित्सकीय मूल्यांकन और क्लिनिकल निर्णय का विकल्प नहीं हैं। थकान एक सामान्य लक्षण है, जबकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस अपेक्षाकृत दुर्लभ बीमारी है। सही निदान के लिए विस्तृत रोग-इतिहास, शारीरिक परीक्षण और विशेषज्ञ व्याख्या आवश्यक है।यह मामला दर्शाता है कि डिजिटल युग में जानकारी आसानी से उपलब्ध है, लेकिन अंतिम पुष्टि, संदर्भ और मानसिक आश्वासन अब भी चिकित्सकीय विशेषज्ञता से ही संभव है।

सफाई कर्मचारियों को दस्ताना देने निर्देश

बिना टोटी वाले नल कनेक्शन को तत्काल काटे : महापौर शशि सिन्हा

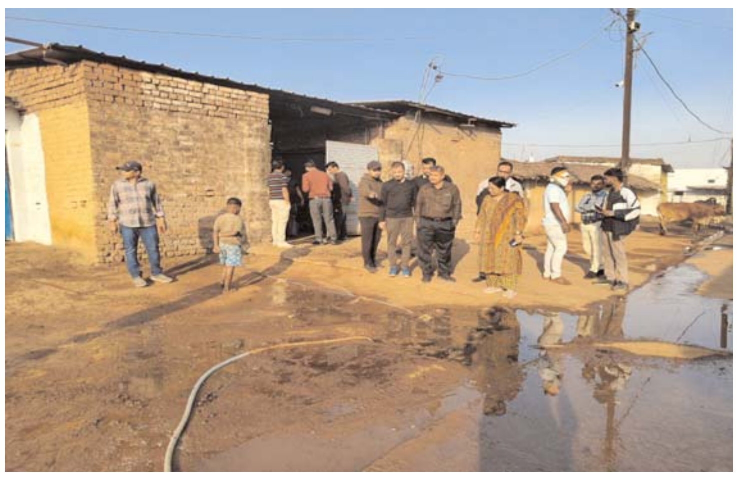

रिसाली। रिसाली महापौर शशि सिन्हा ने निर्देश दिए है कि जिनके घरों के नल पर टोटी नहीं लगा है उनका कनेक्शन तत्काल काटा जाए। सड़क पर बहते पानी को देख महापौर ने यह निर्णय ली। वें वार्ड 33 नेवई बस्ती पूर्व का भ्रमण करते हुए समस्याओं से रूबरू हुई।

नगर पालिक निगम रिसाली महापौर शशि सिन्हा बुधवार की सुबह नेवई बस्ती पहुंची। इस दौरान उन्होंने सड़क पर पानी बहते देख नाराजगी जाहीर की। बाद में खुलासा हुआ कि अधिकांश डेयरी संचालक के घरों में नल कनेक्शन लगा हुआ है जो पानी भरने के बाद नल को खुला छोड़ देते है। इस वजह से पानी सड़क से होते हुए नाली में बह जाता है। महापौर ने इस दौरान ऐसे लोगों पर आक्रोश व्यक्त की, जिन्होंने नल कनेक्शन पाईप में टोटी नहीं लगाया है। महापौर शशि ने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे लोगों को सुचीबद्ध कर पहले समझाईश दे इसके बाद भी असर नहीं होने पर तत्काल नल कनेक्शन विच्छेद की कार्यवाही करे। इस दौरान एमआईसी अनिल देशमुख, संजू नेताम, रोहित धनकर, उप अभियंता जयंत शर्मा, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी अमित चंद्राकर समेत जल विभाग के गोपाल सिन्हा आदि उपस्थित थे।

बिजली विभाग से करें सम्पर्क- भ्रमण के दौरान महापौर को सूचना मिली की बिजली खंभा झुक गया है और दिवार से चिपक गया है। इस वजह से दिवार पर करंट प्रवाहित हो रहा है। महापौर शशि ने इसे गंभीरता से लेते हुए निगम के कर्मचारियों को निर्देश दिए कि बिना विलंब किए विद्युत वितरण कंपनी से सम्पर्क कर समस्या को दूर करें।

सफाई कर्मचारियों को दे संसाधन- महापौर ने भ्रमण के दौरान सफाई व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने सफाई कार्य करने वाले कर्मचारियों से बातचीत की। बिना दस्ताना के सफाई कार्य किए जाने पर स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि एजेंसी से चर्चा उपरांत स्वच्छता दीदी व सफाई कामगार को दैनिक कार्य के लिए उचित संसाधन उपलब्ध कराए।

शासकीय कन्या महाविद्यालय दुर्ग में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़; महापौर ने किया उद्घाटन

दुर्ग। शहर के शासकीय कन्या महाविद्यालय में सोमवार से सात दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (FDP) का भव्य शुभारंभ हुआ। 18 से 24 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य विषय ÷लैंगिक समानता के राजदूत के रूप में संकाय सदस्यों का उन्नयन÷ रखा गया है।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दुर्ग नगर निगम की महापौर अल्का बाघमार रहीं। उन्होंने विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जनभागीदारी अध्यक्ष प्रीति साहू भी उपस्थित रहीं। अतिथियों ने विषय की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षक ही समाज में लैंगिक समानता के सच्चे वाहक बन सकते हैं। उन्होंने इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए महाविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं दीं।

पुस्तक विमोचन और पद्मश्री फूलबासन बाई का सम्मान- उद्घाटन सत्र के दौरान एक विशेष उपलब्धि के रूप में कार्यक्रम संयोजक डॉ. रेशमा लाकेश द्वारा लिखित पुस्तक ÷तनाव प्रबंधन÷ का विमोचन अतिथियों के कर-कमलों द्वारा किया गया। इसके साथ ही, महिला सशक्तिकरण की प्रतीक और प्रसिद्ध समाजसेवी पद्मश्री फूलबासन बाई यादव को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक, अतिथि व्याख्याता, कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। सात दिनों तक चलने वाले इस बौद्धिक विमर्श में विभिन्न सत्रों के माध्यम से लैंगिक संवेदीकरण पर चर्चा की जाएगी।

अंबागढ़ चौकी के हितागुटा ग्राम में सामुदायिक शौचालय का लोकार्पण, स्वच्छता की दिशा में अहम कदम,ग्रामीणों को मिलेगी सुविधा, स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वच्छता

मोहला। जनपद पंचायत अंबागढ़ चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत हितागुटा के ग्राम ठेठवारलझिया क्रमांक-3 में गत दिवस नवनिर्मित सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्रामवासियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही।उद्घाटन अवसर पर ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती सरोज मंडावी, ग्राम पटेल तथा जनपद पंचायत अंबागढ़ चौकी के अनुविभागीय अधिकारी श्री आकाश सोनकर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके साथ ही तकनीकी सहायक एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत विकासखंड समन्वयक ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की। नवनिर्मित सामुदायिक शौचालय का निर्माण ग्रामीणों की सुविधा, स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सुविधा के प्रारंभ होने से खुले में शौच की समस्या दूर होगी एवं सम्मानजनक जीवनशैली को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान ग्रामवासियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए जिला प्रशासन एवं ग्राम पंचायत के प्रति आभार व्यक्त किया।

जिले में महिलाओं को आजीविका से जोड़ने विशेष पहल, स्व-सहायता समूहों को मिल रहा प्रोत्साहन

मोहला। जिले के समग्र विकास में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाने की दिशा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित कर महिलाओं को विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। विशेष रूप से समूहों को वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण, संधारण एवं विपणन से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 13 फरवरी को सीईओ जिला पंचायत श्रीमती भारती चंद्राकर द्वारा विकासखंड मानपुर के खड़गांव संकुल अंतर्गत भ्रमण किया गया। ग्राम पंचायत दोरबा में आईडब्लूएमपी योजना के तहत आयोजित बैठक में 08 ग्राम संगठनों के अध्यक्ष, सचिव एवं स्व-सहायता समूह की लगभग 77 महिलाओं से संवाद स्थापित किया गया। इस दौरान महिलाओं को वनोपज आधारित आजीविका गतिविधियां जैसे संग्रहण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं बाजार में विपणन के लिए प्रेरित किया गया। भ्रमण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) अंतर्गत ग्राम बोरिया में संचालित ठेकेदारी आजीविका डबरी का निरीक्षण कर कार्य की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। सीईओ जिला पंचायत ने महिलाओं को शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़कर स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर विकसित करने पर विशेष जोर दिया। इस पहल से न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है, बल्कि जिले के समावेशी एवं सतत विकास को भी नई गति मिल रही है।

जनदर्शन में कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने आमजन की सुनीं समस्याएं , जनदर्शन में 45 आवेदन प्राप्त हुए

बेमेतरा। जिले में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाले जनदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत बीते सोमवार को कलेक्टरेट स्थित दृष्टि सभा कक्ष में जनदर्शन का आयोजन किया गया। जनदर्शन में कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। जनदर्शन के दौरान नागरिकों ने अपनी विभिन्न मांगों, शिकायतों एवं समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा। कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशीलता के साथ संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को दूरभाष पर एवं समक्ष बुलाकर प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। कई प्रकरणों का समाधान मौके पर ही किया गया।सोमवार को आयोजित जनदर्शन में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 45 आवेदन प्राप्त हुए। तात्कालिक महत्व के मामलों का प्राथमिकता से निराकरण किया गया, जबकि गंभीर एवं जांच योग्य आवेदनों को समय-सीमा (टीएल) पंजी में दर्ज कर नियमानुसार शीघ्र निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। जनदर्शन में निराश्रित एवं वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बैटरी चलित ट्रायसायकल, प्रधानमंत्री आवास योजना, कटा हुआ रकबा जोड़ने, खाद गड्ढा हटाने, आम रास्ता खुलवाने सहित अन्य जनहित से जुड़े विषयों पर आवेदन प्राप्त हुए।

महाशिवरात्रि पर अटल आवास में नव निर्मित शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा

बीजापुर। महाशिवरात्रि के अवसर पर अटल आवास, चिकटराज वार्ड क्रमांक-14 में नव निर्मित शिव मंदिर की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। अटल आवास मंदिर समिति की ओर से आयोजित यह दो दिवसीय कार्यक्रम शनिवार और रविवार को संपन्न हुआ।शनिवार को बीजापुर के गायत्री मंदिर से शिवलिंग को बाजा-गाजा और डीजे के साथ शोभायात्रा निकालकर नए मंदिर तक लाया गया। यात्रा के दौरान पूरा वार्ड भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। जगह-जगह श्रद्धालु शोभायात्रा के स्वागत में खड़े नजर आए। रात में मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन हुआ, जहां देर तक लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन रहे।रविवार सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई।

ग्राम पंचायत गुधेली की सीमा निषाद बनीं लखपति दीदी, मछली पालन से बदल गई जीवन की कहानी

बेमेतरा। ग्राम पंचायत गुधेली की रहने वाली सीमा निषाद, जिन्होंने मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए प्रेरणा का स्त्रोत भी बन गई हैं। सीमा दीदी ÷मां लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह÷ की सदस्य बनकर 2020 में अपने सशक्तिकरण की यात्रा शुरू की। समूह में शामिल होने से पहले दीदी पारंपरिक मजदूरी करती थीं और जीवन के आर्थिक संकट से जूझ रही थीं। लेकिन समूह के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के बाद दीदी ने अपने व्यवसायिक कौशल और नेतृत्व क्षमता को निखारा और नए अवसरों की तलाश शुरू की।

मछली पालन से सशक्तिकरण की कहानी-दीदी ने ग्राम पंचायत में मछली पालन के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके बाद ऋद्ध/ष्टद्बद्ध के माध्यम से ग्राम पंचायत का तालाब किराए पर लिया और मछली पालन के लिए लोन प्राप्त कर तालाब में बीज डाले। मत्स्य विभाग से आवश्यक जाल और उपकरण प्राप्त करने के बाद दीदी ने मेहनत और लगन के साथ अपने तालाब में मछली पालन शुरू किया।

देवबलोदा घटना का विरोध : मुस्लिम समुदाय ने कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन, सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग

दुर्ग। देव बलोदा के ऐतिहासिक शिव मंदिर परिसर में आयोजित महाशिवरात्रि मेले के दौरान हुए विवाद के बाद मुस्लिम समुदाय ने लामबंद होकर जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे और दोषियों के खिलाफकड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा।

दुकान लगाने को लेकर हुआ था विवाद- ज्ञापन सौंपने पहुंचे समाज के लोगों ने बताया गया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर देव बलोदा मेले में मुस्लिम समुदाय के व्यापारियों द्वारा दुकानें लगाई गई थीं। आरोप है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मेले में पहुंचकर इन दुकानों का विरोध किया और व्यापारियों को वहां से हटने के लिए मजबूर किया। समुदाय का कहना है कि वे वर्षो से मेलों में दुकानें लगाते आ रहे हैं और यह आपसी भाईचारे का प्रतीक रहा है।

एफ आई आर और सुरक्षा की मांग- मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि कुछ अराजक तत्व शहर के सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कथित अभद्र व्यवहार की निंदा की और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।

भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि व्यापारी केवल अपना रोजगार चलाने के उद्देश्य से मेले में गए थे। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान समुदाय के प्रमुख सदस्य और प्रभावित व्यापारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

लोकतंत्र प्रहरी मीडिया ग्रुपप एवं एस.आर. हॉस्पिटल एंड कॉलेज दुर्ग के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन

भिलाई। शासकीय अवकाशों के साथ हिन्दू नववर्ष, पर्व-त्योहारों एवं धार्मिक तिथियों की विस्तृत जानकारियों से भरा लोकतंत्र प्रहरी मीडिया ग्रुप एवं एस आर हॉस्पिटल एंड कालेज का वार्षिक कैलेण्डर का शुक्रवार को शांति नगर थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा ने विमोचन किया।

इस दौरान लोकतंत्र प्रहरी मीडिया ग्रुप की इस पहल की सराहना करते हुए पूरी टीम को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं और जनहित में किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की।

लोकतंत्र प्रहरी मीडिया ग्रुप के वीडियो एडिटर हरीश चौधरी टीम के साथ शांति नगर थाना पहुंचकर प्रभारी को नववर्ष की बधाईयों के साथ कैलेण्डर की प्रति सौंपी।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास मेमोरियल सेंटर के बाजू, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित करवाकर व गदा चौक, फरीद नगर रोड स्वर्गीय तुलाराम मेमोरियल स्कूल के पास सुपेला भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-490023 से प्रकाशित। संपादक : संजय तिवारी, मो. 9200000214 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारा न्यायलीन क्षेत्र दुर्ग होगा। Email : loktantraprahrinews@gmail.com